भारत की
कम्युनिस्ट
पार्टी
(मार्क्सवादी)

21वीं पार्टी कांग्रेस के लिए राजनीतिक प्रस्ताव का मसौदा

(केंद्रीय कमेटी की 19-21 जनवरी, 2015, हैदराबाद बैठक द्वारा स्वीकृत)

21वीं पार्टी कांग्रेस के लिए राजनीतिक प्रस्ताव का मसौदा

(केंद्रीय कमेटी की 19-21 जनवरी, 2015, हैदराबाद बैठक द्वारा स्वीकृत)

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति

1.1 देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। मोदी सरकार का आना, भारतीय राजनीति में दक्षिणपंथी बदलाव के सुदृढ़ीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें नवउदारवादी बलाघात तथा हिंदुत्ववादी मुहिम का, साम्राज्यवादपरस्त उन्मुखता के साथ योग हो रहा है। पहले ही इसका असर खुल्लमखुल्ला बड़े-कारोबारीपरस्त नीतियों में देखा जा सकता है, जो सामाजिक असमानताएं और बढ़ाने जा रही हैं तथा मेहनतकश जनता का शोषण और तेज करने जा रही हैं। हिंदुत्ववादी ताकतों के हमले के साथ जुड़कर यह, वर्गीय ताकतों का संतुलन मेहतनकश जनता के पक्ष में बदलने के हमारे लक्ष्य के लिए एक नयी तथा गंभीर चुनौतियां पेश करता है। हालात को समुचित तरीके से समझने के लिए यह जरूरी है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर लिया जाए, जिनका राष्ट्रीय परिस्थिति पर सीधे-सीधे असर पड़ने जा रहा है।

1.2 पार्टी की 20वीं कांग्रेस के बाद की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की पहचान निम्नलिखित से होती है:

(1) 2008 की विश्व वित्तीय मंदी से एक अनिश्चित तथा कमजोर बहाली।

(2) दुनिया भर में अपनी वर्चस्वशाली भूमिका बनाए रखने की अमरीका की लगातार जारी कोशिशें। अमरीका ऐसा सैन्य हस्तक्षेपों के जरिए कर रहा है और वित्तीय व बैंकिंग प्रणालियों पर अपने नियंत्रण, रिजर्व मुद्रा के रूप में डालर की भूमिका तथा अति-महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के जरिए,

विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में अपनी प्रभुत्वशाली भूमिका के माध्यम से कर रहा है।

(3) पश्चिम एशिया में इराक, लीबिया तथा सीरिया में अमरीका के नेतृत्ववाले हस्तक्षेपों के विनाशकारी परिणाम, जिनके चलते बड़ी संख्या में जनहानि हुई है और इस्लामवादी उग्रवाद में उभार आया है।

(4) अमरीकी तथा नाटो बलों के पूर्व की ओर तथा विशेष रूप से यूक्रेन में विस्तार के चलते, रूस से टकराव का नया चक्र।

(5) अमरीका का एशिया पर ध्यान केंद्रित करना और इसके चलते उसके रणनीतिक तथा सैन्य पैंतरे, जिनका मकसद चीन की बढ़ती शक्ति तथा प्रभाव पर अंकुश लगाना है।

(6) रूस तथा चीन के बीच बढ़ता हुआ रणनीतिक सहयोग; पारस्परिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स देशों के कदम; लातीनी तथा दक्षिणी अमरीका में क्षेत्रीय सहयोग; इस सब के चलते बहुध्रुवीयता के रुझान का मजबूत होना।

(7) योरप में कटौतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष तथा जनांदोलन और नयी वामपंथी व जनप्रिय पार्टियों व आंदोलनों का उदय।

(8) वामपंथी नेतृत्ववाली सरकारें, जिन्होंने वेनेजुएला की तरह बढ़ते हुए साम्राज्यवाद-समर्थित विरोध के सामने संघर्ष जारी रखा है। उन्होंने एक वैकल्पिक रास्ते के लिए अपना समर्थन बनाए रखा है, जैसे बोलीविया, उरुग्वे तथा इक्वाडोर में।

विश्व अर्थव्यवस्था

1.3 इस समय जारी आर्थिक संकट कोई अलग-थलग परिघटना नहीं है। यह एक व्यवस्थागत संकट है, जिसकी जड़ें गहराई से पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्निहित नियमों में जमी हुई हैं। अंधाधुंध ऋण दिए जाने तथा सट्टाबाजार के चलते 2007-08 में वित्तीय संकट फूटा और इसके चलते पैदा हुआ साखहीन ऋणों का संकट, संप्रभु (राष्ट्रीय) दीवालों की ओर ले गया। इसका अगला चरण था, शासनों द्वारा बैंकों तथा वित्तीय कार्पोरेशनों के लिए विशालकाय बेलआउट पैकेज दिए जाने का। इसका नतीजा यह हुआ कि कार्पोरेट ऋण, संप्रभु ऋणों में बदल गए और इससे संकट का एक और चरण निकला। संकट के एक के बाद एक आए इन चरणों पर काबू पाने के लिए सत्ताधारी वर्गों द्वारा जो कदम उठाए गए, उनसे मेहनतकश जनता का शोषण बढ़ा है और उसकी आजीविका व सामाजिक कल्याण पर हमले

तेज हुए हैं।

1.4 संकट के मौजूदा चरण में सरकारें 'कमखर्ची के कदम' थोपने के जरिए, खर्चों में भारी कटौतियां कर रही हैं। यह मेहनतकश जनता के कठिनाई से जीते अधिकारों पर नंगा हमला है। उनके आर्थिक अधिकारों पर इस हमले के साथ ही साथ, उनके सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों पर भी हमला हो रहा है। यह अगले संकट के लिए बीज बो रहा है, जहां जनता की क्रय शक्ति में इसके चलते पैदा होने वाली गिरावट, इस पहले ही जारी संकट को और बढ़ा रही होगी।

1.5 इसी पृष्ठभूमि में तथाकथित आर्थिक बहाली अगर कहीं देखने में भी आ रही है, तो सीमित क्षेत्र में (मुख्यत: अमरीका में) ही देखने में आ रही है और वहां भी बहाली कमजोर है तथा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के आंकड़ों में ही ज्यादा दिखाई दे रही है, न कि रोजगार के रुझानों में। दूसरी ओर, योरप अब भी मंदी से गुजर रहा है और जापान के खराब दीर्घावधि वृद्धि रिकार्ड में और गिरावट ही देखने को मिली है। इस सबसे बढ़कर तथाकथित ''उदीयमान बाजारों'' में, खासतौर पर चीन तथा भारत में, जिनसे अन्यत्र नीची वृद्धि दर की भरपाई करने की उम्मीद की जाती थी, हाल के दौर में वृद्धि दरें धीमी पड़ी हैं।

1.6 2009 के बाद से विश्व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि औसतन, मंदी से पहले के दौर के सिर्फ 40 फीसद के बराबर और दीर्घावधि औसत के सिर्फ 60 फीसद के बराबर रही है। विश्व पूंजीवाद के उत्पादक क्षेत्रों में वृद्धि बहुत धीमी गति से हो रही है। अंक्टाड की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार 2012 तथा 2013, दोनों ही वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था सिर्फ 2.3 फीसद की दर से बढ़ी थी। 2014 में उसका प्रदर्शन कोई खास बेहतर रहने की उम्मीद नहीं है। सिर्फ चीन के ही 2014 तथा 2015 में 7 फीसद की वृद्धि दर दर्ज कराने की उम्मीद की जाती है।

1.7 मंदी की भंगुरता को विभिन्न दूसरे कारक बढ़ा रहे हैं, जो अपना असर दिखा रहे हैं। अमरीका में परिमाणात्मक ढील यानी डालर ऋणों में ढील के घटाए जाने का वृद्धि पर और ''उदीयमान'' अर्थव्यस्थाओं के भुगतान संतुलन के पहलू से स्थिति पर, प्रतिकूल असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में भारी गिरावट, कई कारकों के योग का नतीजा है, जैसे आर्थिक मंदी के चलते तेल की मांग में कमी, शेल गैस के निकाले जाने के चलते अमरीका में तेल उत्पादन में बढ़ोतरी और इन परिस्थितियों में तेल के

उत्पादन में कटौती करने के प्रति साऊदी अरब की अनिच्छा। तेल की कीमतों में गिरावट का रूस, ईरान तथा वेनेजुएला पर असर भी दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतों में गिरावट से विश्व बहाली की अनिश्चितताएं और बढ़ गयी हैं। यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक, दुनिया भर में बढ़ते राजनीतिक तनावों के चलते 2015 में विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाएं अच्छी नहीं हैं, हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए संभावनाएं अलग-अलग तरह की हैं।

1.8 नवउदारवादी पूंजीवाद ने बदतरीन असमानताएं पैदा की हैं। विश्व संपदा पर ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की करीब आधी संपदा सिर्फ एक फीसद आबादी के हाथों में है। दुनिया के एक फीसद सबसे धनियों की कुल संपदा 1100 खरब डालर बैठेगी। यह नीचे की ओर से दुनिया की 50 फीसद आबादी की कुल संपदा का 65 गुना होता है। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओ ई सी डी) की रिपोर्ट के अनुसार, अमरीका में सबसे धनी 10 फीसद की औसत आय, सबसे गरीब दस फीसद से 16 गुना ज्यादा है। ओ ई सी डी के ज्यादातर देशों में सबसे अमीर और सबसे गरीब तबकों के बीच का अंतर आज जिस ऊंचाई पर है, पिछले तीस साल में कभी नहीं रहा।

1.9 इस संकट तथा मंदी के जवाब में सत्ताधारी वर्ग, श्रम का शोषण बढ़ाने में और सार्वजनिक खर्चों में कटौतियां करने में लगा रहा है। श्रम के शोषण के तेज किए जाने का पता इस तथ्य से चल जाता है कि 1999 से 2013 के बीच विश्व स्तर पर वास्तविक मजदूरी में बढ़ोतरी, श्रम उत्पादकता में बढ़ोतरी से पीछे बनी रही है। सच तो यह है कि वास्तविक मजदूरी में ज्यादातर बढ़ोतरी, चीन में हुई बढ़ोतरी के चलते ही दर्ज हुई है और अगर इसमें से चीन में हुई वास्तविक मजदूरी में बढ़ोतरी को निकाल दिया जाए, तो वास्तविक मजदूरी में बढ़ोतरी 2012 में सिर्फ 1.3 फीसद बैठेगी और 2013 में 1 फीसद ही। (ग्लोबल वेज रिपोर्ट, 2014-15, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन)

1.10 संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन, 'वर्ल्ड इकॉनमिक स्टडीज़ एंड प्रॉस्पैक्ट्स-2014' के अनुसार विकसित देशों में बेरोजगारी 8.4 फीसद के ऊंचे स्तर पर ही बनी हुई है। योरपीय यूनियन के देशों में बेरोजगारी और भी ज्यादा है, 11 फीसद के स्तर पर। ये सरकारी आंकड़े भी बेरोजगारी को बहुत ही कम कर के दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार युवाओं की बेरोजगारी, बेरोजगारी के सकल आंकड़े से दोगुनी ज्यादा है। 20वीं कांग्रेस

के बाद गुजरे तीन वर्षों में समूची पूंजीवादी दुनिया में बेरोजगारी लगातार ऊंचे स्तर पर बनी रही है, बेरोजगारी का औसत काल लंबा बना रहा है और काम से होने वाली कमाइयां कम बनी रही हैं।

वर्चस्व बनाए रखने की कोशिशें

1.11 अपनी आर्थिक शक्ति में दीर्घावधि गिरावट और खासतौर पर 2008 के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में, साम्राज्यवादी गुट के नेता की हैसियत से अमरीका को नयी चुनौतियों तथा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इराक से शुरू कर उसके सैन्य हस्तक्षेप, उसके नियंत्रण में पश्चिम एशिया को स्थिर करने का उसका रणनीतिक लक्ष्य पूरा करने में विफल रहे हैं। पूर्व की ओर अमरीकी-नाटो बढ़ाव के सामने, रूस अपना जोर दिखाता रहा है। चीन के दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा बड़ी ताकत बनकर सामने आने से, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमरीका के वर्चस्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। अमरीका के लिए, विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संगठनों पर अपनी मनमर्जी लादना भी आसान नहीं रहा है।

1.12 अमरीका ने पश्चिमी एशिया में सैन्य हस्तक्षेप जारी रखने के जरिए, एशिया के लिए अपनी रणनीतिक धुरी के जरिए और यूक्रेन जैसे सोवियत संघ के पूर्व-गणराज्यों में पश्चिम के प्रभाव का विस्तार करने के मामले में रूस से अपना टकराव बढ़ाने के जरिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश की है। वह विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपनी प्रभुत्वशाली भूमिका बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव पर तथा उसके अन्य अर्थव्यवस्थाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर अंकुश लगाने को लक्ष्य बनाकर, अमरीका ने दो प्रमुख व्यापार संधियां शुरू की हैं, जिनके दायरे में विश्व अर्थव्यवस्था का दो-तिहाई हिस्सा आ जाता है। ये संधियां एशिया-प्रशांत क्षेत्र और योरपीय यूनियन के लिए हैं।

1.13 पिछले दो दशकों से ज्यादा में अफगानिस्तान, इराक, लीबिया तथा सीरिया में जो अमरीकी-नाटो सैन्य हस्तक्षेप हुए हैं, उनका सत्यानाशी प्रभाव इस दौर में सामने आया है। सैन्य शक्ति के बल पर इराक तथा लीबिया की तानाशाहीपूर्ण किंतु धर्मनिरपेक्ष सरकारों को पलटे जाने के नतीजे राष्ट्रीय संप्रभुता के नष्ट होने, बड़े पैमाने पर हिंसा और इस्लामवादी अतिवादी ताकतों के उभार के रूप में सामने आए हैं। सीरिया में अमरीका तथा उसके सहयोगियों की दखलंदाजी ने गृहयुद्ध के जरिए बड़े पैमाने पर तबाही

करायी है और शासन के विरोधियों में इस्लामवादी अतिवादी ताकतों का बोलबाला कायम हो गया है। अमरीकी साम्राज्यवाद ने ही इराक पर अपने कब्जे के जरिए, लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ इस्लामवादी सेनाओं की मदद करने के जरिए और सीरिया में (अमरीका के सहयोगी, साऊदी अरब, तुर्की तथा कतर के साथ मिलकर) इस्लामवादी अतिवादी ताकतों को मदद देने के जरिए, आइ एस आइ एस (इस्लामिक स्टेट आफ इराक एंड सीरिया) जैसी ताकतों के उभार के लिए स्थितियां बनायी हैं। अमरीकी नीति के परस्पर विरोधी पक्ष इस तथ्य में खुलकर सामने आ जाते हैं कि एक ओर तो अमरीका इराक तथा सीरिया में आइ एस आइ एस के ठिकानों पर बम बरसा रहा है और दूसरी ओर उसके ही अरब सहयोगी, जमीनी स्तर पर सीरिया में इस्लामवादी ताकतों की मदद कर रहे हैं।

1.14 अमरीकी हस्तक्षेपों का मकसद यह भी था कि ट्यूनीशिया तथा मिस्र में जन-विद्रोहों की जो लहर शुरू हुई थी, उसे दबाया जाए तथा भटकाया जाए। लीबिया तथा सीरिया में अमरीका तथा साऊदी अरब व कतर जैसे उसके सहयोगियों के हस्तक्षेपों ने, तत्ववादी शक्तियों को ही उन्मुक्त किया है। मिस्र में, जहां जन-विद्रोह ने मुबारक निजाम को हटा दिया था, मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार के हटाए जाने के बाद, सैन्य तानाशाही के शासन की वापसी हो गयी है।

1.15 अफगानिस्तान के मामले में, हालांकि राष्ट्रपति ओबामा ने 2014 के आखिर तक अमरीकी सेनाएं वापस बुलाए जाने का एलान किया था, आगे चलकर अमरीका ने वहां अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने का एलान किया है। नयी अफगान सरकार से समझौता किया गया है कि अफगानिस्तान के सैनिक अड्डों में 13 हजार अमरीकी-नाटो सैनिक बने रहेंगे।

1.16 अमरीका, इस्राइल को अपना पूरा-पूरा समर्थन देता है। दक्षिणपंथी इस्राइली सरकार ने अरब देशों में चल रही उथल-पुथल का फायदा उठाकर, गाज़ा पर नृशंस हमले के एक के बाद एक, दो चक्र छेड़े हैं, जिनमें औरतों तथा बच्चों समेत सैकड़ों लोग मारे गए हैं और बड़े पैमाने पर असैनिक संपत्तियां नष्ट हुई हैं। पश्चिमी तट पर उसने अपनी बस्तियों का विस्तार किया है। एक यहूदी राष्ट्र के एलान के कदम शुरू किए गए हैं।

1.17 अमरीका ने इंटरनैट तथा दूरसंचार की निगरानी तथा टैपिंग के जरिए एक विश्व जासूसी व्यवस्था कायम की है जो देशों की, सरकारों की, संगठनों

की तथा व्यक्तियों की जासूसी करती है। यूनाइटेड किंगडम की मदद से अमरीका राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के नाम पर, नंगई से यह जासूसी कर रहा है। यह सीधे-सीधे देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

यूक्रेन

1.18 नाटो के पूर्व की ओर प्रसार के हिस्से के तौर पर यूक्रेन को निशाना बनाया गया है। अमरीका तथा योरपीय यूनियन ने, यूक्रेन की निर्वाचित सरकार को पलटने के आंदोलन को समर्थन दिया था ताकि यूक्रेन को पश्चिमी प्रभाव क्षेत्र में लाए जाने को आसान बनाया जा सके। उन्होंने परोक्ष रूप से नव-नाजी सेनाओं को मान्यता दी थी। इसके नतीजे में पूर्वी यूक्रेन के रूसी-भाषी हिस्सों में बगावत हो गयी। इसके बाद अमरीका तथा योरपीय यूनियन ने रूसी सत्ताओं तथा प्रमुख कारोबारी संस्थाओं पर और राजनीतिक हस्तियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। जवाब में रूस ने योरप तथा अमरीका से खाद्य आयातों पर पाबंदी लगा दी। डोनेत्स तथा लुगान्स्क की सरकारों को पलटने में विफल रहने के बाद, युद्धविराम समझौते पर दस्तखत किए गए। बहरहाल, अमरीका तथा नाटो शक्तियां, रूस के साथ टकराव तेज करने में लगी हैं। यूक्रेन पर टकराव योरप में प्रमुख पूंजीवादी ताकतों के बीच के अंतर्विरोधों को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें अमरीका तथा योरपीय यूनियन एक ओर हैं और रूस, दूसरी ओर।

एशिया में धुरी

1.19 ओबामा प्रशासन ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में, रणनीतिक बदलाव का एलान किया है। एशिया की इस धुरी को, अमरीका के घनिष्ठ सहयोगियों के साथ सैन्य रिश्ते मजबूत कर और अमरीकी सैन्य बलों का अधिकांश हिस्सा प्रशांत सागर में तैनात कर, आगे बढ़ाया जा रहा है। अमरीका, भारत के साथ अपने सैन्य रिश्ते मजबूत करना चाहता है और चीन की काट के तौर पर जापान के पुनर्सैन्यीकरण को बढ़ावा दे रहा है।

व्यापार समझौते

1.20 बहुपक्षीय समझौतों पर भरोसा करने के बजाय अमरीका, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय समझौतों का सहारा ले रहा है। इसके पीछे उसके दो लक्ष्य हैं,

अपना दबदबा कायम रखना और चीन पर अंकुश लगाना।

1.21 अमरीका ने ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टी पी पी) की शुरूआत की है ताकि सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र खड़ा किया जा सके। इसके जरिए अमरीका तथा उसके एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सहयोगियों के आर्थिक एकीकरण को गहरा किया जाएगा और इसके साथ ही साथ, चीन को इससे बाहर रखकर, उसके आर्थिक प्रभाव की रोक-थाम की जा रही होगी। इस समझौते का मकसद तटकर बाधाओं को दूर करना है, जो दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी तथा बौद्धिक संपत्ति अधिकारों में बदलाव की ओर ले जाएगा और वित्तीय संस्थाओं की ताकत बढ़ाएगा।

1.22 इसके साथ ही साथ योरपीय यूनियन और अमरीका के बीच ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप (टी टी आइ पी) के लिए वार्ताएं हो रही हैं, जिसे अमरीका टी पी पी का पूरक समझौता मानता है। जब वार्ताएं पूरी हो जाएंगी, योरपीय यूनियन और अमरीका का यह समझौता, अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बन जाएगा। इस समझौते से कार्पोरेटों की ताकत बढ़ जाएगी और सरकारों के लिए बाजारों का नियमन करना और मुश्किल हो जाएगा।

जापान

1.23 शिंजो एबे की सरकार ने जापान के संविधान के अंतर्गत उसकी सेना की भूमिका की व्याख्या ही बदलने के जरिए, जापानी सेना की भूमिका बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। अमरीका के समर्थन से एबे जापान की प्रतिरक्षा सामर्थ्य तथा शस्त्र उत्पादन को बढ़ा रहा है। जापान, पूर्वी चीन सागर में कुछ द्वीपों पर चीन के साथ विवाद में और ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहा है। एबे के संसदीय चुनाव जीतने के बाद आस्ट्रेलिया तथा भारत के साथ घनिष्ठतर सुरक्षा गठबंधन कायम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इन कदमों का मकसद अमरीका-जापान-आस्ट्रेलिया तथा भारत के बीच चतुष्कोणीय गठजोड़ कायम करना है।

1.24 इसके साथ ही साथ अमरीका ने दक्षिणी कोरिया के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत किया है तथा उसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़े हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर कंजर्वेटिव पार्टी का कब्जा होने के बाद से, तनाव कम करने और उत्तरी कोरिया के साथ वार्ताएं फिर से शुरू करने के प्रयासों को धक्का लगा है।

बढ़ती बहुध्रुवीयता

1.25 ब्रिक्स देशों—ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका—ने अपने सहयोग को संस्थागत आधार पर ठोस रूप देने के लिए और कदम उठाए हैं। ब्राजील में हुए छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने एक नये विकास बैंक (एन डी बी) तथा कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट (आपात संचित प्रबंध) की स्थापना की है। एन डी बी को अगर विश्व बैंक की तर्ज पर नहीं चलाया जाता है, तो उसके सकारात्मक भूमिका अदा करने की संभावनाएं हैं। राजनीतिक मोर्चे पर, सीरिया तथा ईरान जैसे महत्वपूर्ण सवालों पर, ब्रिक्स ने अमरीका के रुख से असहमति जतायी है और सैन्य हस्तक्षेप का विरोध किया है। इन सीमाओं के बावजूद, इनमें से ज्यादातर देशों की सरकारों की प्रकृति को देखते हुए, ब्रिक्स मंच का सुदृढ़ होना, बहुध्रुवीयता के बढ़ते रुझान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

1.26 शांघाई सहयोग संगठन, कम्यूनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरीबियन स्टेट्स (सीईएलएसी), बोलीवारियन एलाइंस फॉर द पीपुल ऑफ ऑवर अमेरिका (अल्बा), यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन्स (उनासुर) जैसे पहले से कायम क्षेत्रीय संगठनों ने अपने सहयोग के क्षेत्र का और विस्तार किया है। ब्रिक्स के साथ ही चीन की पहल पर गठित एशियाई ढांचागत निवेश बैंक जैसे अन्य क्षेत्रीय सहयोग निकाय गठित किए जा रहे हैं। भारत समेत 21 देश इस एशियाई ढांचागत विकास बैंक के सदस्य हैं। इन सभी क्षेत्रीय मंचों तथा संस्थाओं से, बहुध्रुवीयता के रुझान को बल मिल रहा है।

कटौती के कदमों के खिलाफ जनसंघर्ष

1.27 विश्व वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में विभिन्न संघर्ष तथा प्रतिरोध आंदोलन सामने आए हैं। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन के बाद, अनेक देशों में कटौती के कदमों के खिलाफ विरोध कार्रवाइयां जारी रही हैं। ग्रीस में ट्रेड यूनियन कान्फेडरेशन, पामे के नेतृत्व में मजदूर वर्ग की बड़ी-बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। कटौती के कदमों और योरपीय यूनियन के बेल आउट पैकेज का विरोध करने वाला एक नया वामपंथी संगठन, सिरजा उभरकर सामने आया है। 2015 की जनवरी में हुए संसदीय चुनाव में उसकी जीत हुई है। उसे संसद की कुल 300 सीटों में से 149 सीटें मिली हैं और 36 फीसद वोट मिला है। यह एक उल्लेखनीय राजनीतिक घटनाविकास है। स्पेन ने इंडिग्नेडोस (क्रुद्धों का) आंदोलन जारी रहा है और पोदेमोस नाम की एक

राजनीतिक ताकत उभरकर आयी है, जो मुख्यधारा की पार्टियों को चुनौती दे रही है। पुर्तगाल में भी मजदूर वर्ग की बड़ी-बड़ी कार्रवाइयां सामने आयी हैं तथा विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसी प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, आइसलैंड तथा बेल्जियम में भी, जनता पर अपनी-अपनी सरकार के हमले के खिलाफ, बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ग की विरोध कार्रवाइयां हुई हैं। एक और क्षेत्र जहां मजदूरों की जुझारू हड़तालें व कार्रवाइयां हो रही हैं, दक्षिण अफ्रीका है। इनमें प्लेटीनम तथा अन्य खदान मजदूरों की हड़तालें खास हैं। अमरीका में फर्गूसन की घटना के बाद, जिसने विभिन्न शहरों में काले युवकों के नस्लवादी तरीके से गोली से उड़ाए जाने को रेखांकित किया है, बड़े पैमाने पर विरोध कार्रवाइयां हुई हैं।

1.28 कटौती के कदमों के खिलाफ जन-असंतोष बढ़ा है और इसकी अभिव्यक्ति योरपीय यूनियन की संसद के चुनाव में हुई है, जिसमें लोगों ने इन कदमों को लागू कर रही अपने-अपने देश की सरकारों के खिलाफ नाराजगी जतायी है। इसके साथ ही साथ धुर-दक्षिणपंथी ताकतें भी सक्रिय रही हैं और उन्होंने अपने परदेशी-द्वेष, प्रवासीविरोधी मंच तथा योरपयी यूनियन के खिलाफ अपनी भाषणबाजी के जरिए, अपनी ताकत बढ़ायी है। ग्रीस, इटली, नीदरलैंड्स तथा फ्रांस में ऐसी ताकतें आगे बढ़ी हैं।

प्रतिक्रियावादी आंदोलनों का उभार

1.29 दुनिया भर में तत्ववाद, परदेशी-द्वेष तथा संकीर्णतावादी कट्टरता के सबसे जहरीले रूपों का फैलाव हुआ है। हाल के दौर में पश्चिम एशिया में आइ एस आइ एस तथा अन्य अतिवादी शक्तियों का और नाइजीरिया में बोको हराम का, सोमालिया व उत्तरी अफ्रीका में इस्लामवादी तत्ववादियों का, श्रीलंका व म्यांमार में बौद्ध कट्टरपंथी गुटों का और योरप में घोर-दक्षिणपंथी नव-नाजी पार्टियों का उभार हुआ है। यह सब साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का भी फल है और समाजवाद को धक्के लगने के बाद से सार्वभौम प्रगतिशील मूल्यों के पीछे धकेले जाने का भी।

पर्यावरण परिवर्तन

1.30 लीमा में हुए आखिरी से पहले पर्यावरण शिखर सम्मेलन में कमजोर नतीजे निकाले जाने के बाद, जोकि जान-बूझकर अमरीका के नेतृत्व में विकसित देशों ने कराया है, 2015 के दिसंबर में होने वाले पेरिस शिखर सम्मेलन के लिए पीठिका तैयार कर दी गयी है। इस शिखर सम्मेलन में एक नये विश्व

समझौते को अंतिम रूप दिया जाना है, जो क्योटो प्रोटोकाल की जगह लेगा। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अमरीका तथा अन्य विकसित पूंजीवादी देश, अंतत: अधिकांश पर्यावरणीय शामलात की गुंजाइशों पर कब्जा कर लेंगे और विकासशील देशों के लिए विकास करने तथा अपनी जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाने की बहुत कम गुंजाइश रह जाएगी। ''साझा किंतु भिन्नीकृत जवाबदारी'' (सी बी डी आर) सिद्धांत के उल्लेखनीय तरीके से कमजोर किए जाने के जरिए, विकसित तथा विकासशील देशों के बीच समता के सिद्धांत को झटके के साथ छोड़ दिया गया है। 2020 से आगे के लिए पेरिस समझौते का आधार, उत्सर्जन नियंत्रण के ऐसे ढांचे के ही बनाए जाने की ज्यादा संभावना है, जो स्वैच्छिक वचनबद्धताओं पर आधारित होगा, जिनके लिए अमरीका जोर लगाता आया है। अमरीका तथा अन्य विकसित देशों की मौजूदा वचनबद्धताएं, जो जरूरत से बहुत घटकर हैं, पृथ्वी पर ताप में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी की ओर ले जाएंगी, जबकि सहमत लक्ष्य विश्व ताप में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने का था। इसके खासतौर पर विकासशील देशों के लिए और दुनिया भर में गरीबों के लिए सत्यानाशी परिणाम होंगे।

लातीनी अमरीका: वामपंथ की प्रगति

1.31 राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के निधन से लगे धक्के के बावजूद, वेनेजुएला ने तथा लातीनी अमरीका की वामपंथी सरकारों ने, नवउदारवाद तथा साम्राज्यवाद को चुनौती देने वाले वैकल्पिक रास्ते पर बढ़ने के लिए संघर्ष जारी रखा है। वेनेजुएला को आर्थिक रूप से भी और अमरीका-समर्थित विषाक्त दक्षिणपंथी विपक्ष के चलते भी, कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद, वेनेजुएला सस्ते खाद्य स्टोर, मुफ्त भोजन लंगर, समुदायों के बीच मुफ्त स्वास्थ्य केंद्रों का ताना-बाना स्थापित करने तथा मुफ्त शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और बिजली तथा पीने के पानी जैसी बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने की नीतियों पर चलता रहा है।

1.32 बोलीविया में मोरालेस सरकार ने तेल तथा गैस क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया है, जिसके चलते गैस से सरकार को हासिल होने वाले राजस्व में 82 फीसद की भारी बढ़ोतरी हुई है। दूरसंचार तथा बिजली को भी राजकीय क्षेत्र में ले लिया गया है। बोलीविया ने समूचे लातीनी अमरीका में गरीबी घटाने की सबसे ऊंची दर हासिल की है और 2012 से गरीबी में 32.2

फीसद कमी दर्ज करायी है। इक्वाडोर में शिक्षा पर खर्च दोगुना हो गया है और सकल घरेलू उत्पाद के 2.6 फीसद से बढ़कर 5.2 फीसद पर पहुंच गया है। पिछले पांच साल में वास्तविक न्यूनतम मजदूरी में 40 फीसद बढ़ोतरी हुई है। 2009 से गरीबी में नाटकीय तरीके से गिरावट आयी है और पिछले पांच साल में उसमें चौथाई की कमी हो गयी है।

1.33 पिछले तीन साल में हुए चुनावों में वामपंथी सरकारें दोबारा जनादेश हासिल कर चुनी गयी हैं। बोलीविया में राष्ट्रपति इवो मोरालेस को 61.6 फीसद वोट के साथ दोबारा चुना गया है। इक्वाडोर, उरुग्वे तथा निकारागुआ में दोबारा वामपंथी सरकारें दोबारा चुनकर आयी हैं। दक्षिणी अमरीका के सबसे बड़े देश, ब्राजील में डिल्मा रूसेफ, दक्षिणपंथी ताकतों की सम्मिलित चुनौती को परास्त करते हुए, दोबारा राष्ट्रपति चुनी गयी हैं।

1.34 मोटे तौर पर लातीनी अमरीका में वामपंथ की प्रगति को बनाए रखा जा सका है। क्यूबा तथा अमरीका के संबंध सामान्य करने के कदम उठाए जाने की हाल में आयी घोषणा को दक्षिणी अमरीका के सभी देशों की इस सर्वसम्मत राय की पृष्ठभूमि में ही देखा जाना चाहिए कि क्यूबा को अलग-थलग न किया जाए। अमरीका इस राय को अनदेखा नहीं कर पाया है।

समाजवादी देश

1.35 चीन ने, जो कि पिछली कांग्रेस के समय पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आ चुका था, प्रगति जारी रखी है। 2012 के बाद से जो रास्ता अपनाया गया है उसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के बजाय वहनीय विकास तथा विकास की गुणवत्ता पर ही जोर है। वहां चल रहे आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्गठन को देखते हुए, चीन का 2014 में 7.4 फीसद वृद्धि दर दर्ज कराना उल्लेखनीय है। वियतनाम ने पिछले तीन वर्षों में आर्थिक वृद्धि दर्ज करायी है, जिसकी पहचान निर्यातों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी से होती है। वहां गरीबी घटाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। गरीबी की राष्ट्रीय दर जो 2005 में 22 फीसद थी, 2013 तक घटकर 7.8 फीसद रह गयी, हालांकि असमानता अब भी बढ़ रही है। कोरियाई जनवादी गणराज्य ने अपने खिलाफ थोपी गयी पाबंदियों का सामना किया है और अमरीका तथा दक्षिण कोरियाई सरकार के उकसावेपूर्ण कदमों की उसने सफलता के साथ काट की है। क्यूबा 2011 से अपनी आर्थिक व्यवस्था को अद्यतन बनाने और सुधार लागू करने

में लगा हुआ है। क्यूबाई पांच की रिहाई और क्यूबा तथा अमरीका के बीच कूटनीतिक रिश्ते कायम करने के निर्णय के रूप में, क्यूबा की बड़ी जीत हुई है। राष्ट्रपति ओबामा ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि पांच दशक से चली आ रही क्यूबा को अलग-थलग करने की नीति विफल रही है।

दक्षिण एशिया

1.36 दक्षिण एशिया के हालात की पहचान इस क्षेत्र की विभिन्न सरकारों द्वारा लागू की जा रही नवउदारवादी नीतियों के चलते मेहनतकश जनता के जीवन स्तर में गिरावट से होती है। पाकिस्तान में, 2012 के संसदीय चुनाव के बाद, नवाज शरीफ की सरकार बनी है। वहां इस दौर में तत्ववादी तथा अतिवादी ताकतों का खतरा बना ही रहा है। पेशावर में स्कूली बच्चों का नृशंस नरसंहार, इस खतरे की मिसाल है। नेपाल में 2013 में दूसरी संविधान सभा बनने के बाद भी, एक नया संविधान बनाने के प्रयास फलीभूत नहीं हो पाए हैं। संविधान के मसौदे के स्वीकार किए जाने के लिए 2015 की जनवरी की समय सीमा निकल गयी है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी तथा तत्ववादी शक्तियों द्वारा युद्ध अपराध ट्रिब्यूनल के अपने कुछ शीर्ष नेताओं को सजा सुनाने के बाद से हिंसक विरोध कार्रवाइयों का सहारा लिया जा रहा है। दक्षिणपंथी तत्ववादी ताकतों द्वारा पेश किए जा रहे खतरे के खिलाफ प्रगतिशील तथा जनतांत्रिक शक्तियां गोलबंदी करती रही हैं, जिसका सबूत शाहबाग आंदोलन में मिला था। श्रीलंका में 2015 की जनवरी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अप्रत्याशित पराजय के साथ, राजपक्षे का राष्ट्रपति-काल समाप्त हो गया। संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार मैत्रीपाल सिरिसेना ने कार्यपालक राष्ट्रपति की व्यवस्था खत्म करने के वादे के साथ राष्ट्रपति पद संभाला है। नयी सरकार के आने से इसकी उम्मीदें पैदा हुई हैं कि गृहयुद्ध के खत्म होने के बाद, छः साल से अनसुलझे पड़े तमिल प्रश्न का कोई राजनीतिक समाधान निकाला जाएगा।

1.37 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), भारत-पाकिस्तान के बीच गतिरोध के चलते, आर्थिक सहयोग व व्यापार की अपनी संभावनाओं को हासिल नहीं कर पाया है। 2014 के नवंबर में कठमंडू में हुए सार्क शिखर सम्मेलन में इसे देखा जा सकता था।

साम्राज्यवादविरोधी एकजुटता

1.38 दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव तथा रणनीतिक रिश्ते बढ़ाने की अमरीका

की सभी तिकड़मों का सी पी आइ (एम) मजबूती से विरोध करेगी। पार्टी दक्षिण एशिया में तमाम वामपंथी, प्रगतिशील तथा साम्राज्यवादविरोधी ताकतों के साथ सहयोग करेगी और उनके साथ अपने रिश्ते मजबूत करेगी।

1.39 इस्राइली कब्जे के खिलाफ और एक स्वतंत्र देश के लिए, फिलिस्तीनी जनगण के संघर्ष को पार्टी अपना पूरा-पूरा समर्थन देगी। पार्टी, इस्राइल के साथ भारत सरकार के सुरक्षा तथा सैन्य गठजोड़ के खिलाफ है।

1.40 पार्टी, समाजवादी देशों—चीन, वियतनाम, क्यूबा, कोरियाई जनवादी गणराज्य तथा लाओस—के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करती है। पार्टी, अमरीका के नेतृत्व में थोपी गयी नाकेबंदी खत्म कराने के लिए क्यूबा की सरकार तथा जनता के संघर्ष को अपना पूरा समर्थन देती है।

1.41 पार्टी, लातीनी अमरीका के वामपंथी व क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ और खासतौर पर वेनेजुएला के साथ, जहां क्रांतिकारी ताकतें साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित दक्षिणपंथी विपक्ष का मुकाबला कर रही हैं, एकजुटता के विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करेगी।

1.42 साम्राज्यवादी हमलों के खिलाफ संघर्ष, साम्राज्यवादी विश्वीकरण द्वारा थोपी जा रही नवउदारवादी व्यवस्था के खिलाफ बहुमुखी संघर्षों और पर्यावरण की रक्षा करने व पर्यावरण न्याय के लिए संघर्ष, इन सभी को आपस में जोड़कर, एक शक्तिशाली साम्राज्यवादविरोधी आंदोलन का निर्माण किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय परिस्थिति

2.1 मई 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से राजनीतिक परिस्थिति में नाटकीय बदलाव आया है। पहली बार भाजपा को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है, हालांकि उसे 31 फीसद वोट ही हासिल हुआ है। इसने एक दक्षिणपंथी हमले के लिए मंच सजा दिया है, जिसमें नवउदारवादी नीतियों का हमलावर तरीके से आगे बढ़ाया जाना और आर एस एस के नेतृत्व में हिंदुत्ववादी ताकतों का अपने सांप्रदायिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए खुलकर प्रयास करना शामिल हैं। इस तरह का परिस्थिति संयोग, बढ़ती तानाशाही की पूर्व-सूचना देता है।

2.2 पार्टी की 20वीं कांग्रेस में, जो 2012 के अप्रैल में हुई थी, यह दर्ज किया गया था कि कांग्रेस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में नवउदारवादी एजेंडा को और आगे ले जा रही थी। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बेनकाब होने और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी तथा बढ़ती बेरोजगारी से, जनता का एक बड़ा हिस्सा और खासतौर पर मध्य वर्ग तथा युवा विमुख हो रहे थे। पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में यह भी दर्ज किया गया था कि सांप्रदायिक राजनीति का खतरा बना हुआ है क्योंकि आर एस एस तथा उसका राजनीतिक बाजू भाजपा, सांप्रदायिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मौके की तलाश में हैं। इसलिए, प्रस्ताव में कांग्रेस और भाजपा, दोनों से ही लड़ने का आह्वान किया गया था। प्रस्ताव में यह भी ध्यान दिलाया गया था कि यूपीए की सरकार हरेक स्तर पर अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही थी। उधर सी पी आइ (एम) पर पश्चिम बंगाल में भारी हमला हो रहा था और आम तौर पर वामपंथ को अलग-थलग करने की कोशिशें की जा रही थीं। 20वीं कांग्रेस ने पार्टी का आह्वान किया था कि अपनी स्वतंत्र भूमिका को बढ़ाए, वामपंथी एकता को मजबूत करे और एक वामपंथी तथा जनतांत्रिक मंच के आधार पर, मजदूर वर्ग, किसानों तथा अन्य तबकों को गोलबंद करे।

2.3 पिछली पार्टी कांग्रेस के बाद के मुख्य घटनाविकास तथा विशेषताएं इस प्रकार हैं:

व्यापक विशेषताएं

(1) यूपीए द्वितीय की सरकार ने आला पदों पर भारी भ्रष्टाचार, अभूतपूर्व महंगाई तथा बढ़ती बेरोजगारी के शर्मनाक रिकार्ड के साथ अपना कार्यकाल समाप्त किया है। इस दौर में नवउदारवादी नीतियों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था। मनमोहन सिंह की सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नये-नये क्षेत्रों के द्वार खोले, जैसे खुदरा व्यापार में और कहीं ज्यादा निजीकरण के दरवाजे खोले।

(2) पिछले दो आम चुनाव हार चुकी भाजपा, इन हालात का पूरा फायदा उठाने में कामयाब हुई। बड़ी पूंजी तथा आर एस एस की पूरी ताकत के बल पर, कार्पोरेट मीडिया की मदद से, नरेंद्र मोदी को कारगर तरीके से ऐसे नेता के रूप में पेश किया गया, जो अच्छा शासन देगा तथा कर के दिखाएगा।

(3) इसके साथ ही साथ, आर एस एस तथा उससे जुड़े संगठन चुनाव से साल भर पहले से ही सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए समर्थन जुटाने में लग गए थे। देश में सांप्रदायिक घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की लहर इसकी आंखें खोलने वाली मिसाल थी।

(4) भाजपा की जीत और मोदी सरकार के आने से, एक दक्षिणपंथी हमला उन्मुक्त हुआ है। कार्पोरेट सत्ता तथा हिंदुत्व की जोड़ीदार शक्तियां, दक्षिणपंथी बदलाव को गति दे रही हैं।

(5) मोदी सरकार के नौ महीनों के दौर की पहचान नवउदारवादी नीतियों के आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाए जाने से होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को बढ़ाए जाने पर जोर है। इस दौर में निजीकरण बढ़ा है। इस दौर में श्रम कानूनों तथा भूमि अधिग्रहण कानूनों को कमजोर किया गया है। हिंदुत्ववादी एजेंडा को थोक में आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक आधार के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

(6) यूपीए-द्वितीय की सरकार की विदेश नीति की दिशा अमरीका के साथ रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की बनी रही थी और इस तरह स्वतंत्र विदेश नीति को नुकसान पहुंचा रही थी। मोदी सरकार इसी रुख को और आगे बढ़ा रही है।

(7) यूपीए सरकार एक के बाद एक भ्रष्टाचार घोटालों में फंसी रही थी, जिसने उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के सवाल को उभारकर सामने ला दिया। इस तरह का भ्रष्टाचार नवउदारवादी निजाम का और बड़ी पूंजी-सत्ताधारी राजनीतिज्ञों-नौकरशाहों की फलती-फूलती जुंडली का व्यवस्थागत परिणाम था।

(8) सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएं और भी बढ़ी हैं। मजदूर वर्ग तथा गरीब किसानों का शोषण और तेज हो गया है। इसकी सबसे ज्यादा मार उन तबकों पर पड़ी है जो पहले ही उत्पीड़ित तथा वंचित हैं—आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक तथा महिलाएं।

(9) विभाजनकारी ताकतों की विघटनकारी गतिविधियां भी सामने आयी हैं, जैसे असम में बोडोलैंड टैरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (बी टी ए डी) इलाके में तथा उससे बाहर बोडो अतिवादी संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर बंगालीभाषी मुसलमानों पर तथा आगे चलकर

आदिवासियों पर हमले। देश के विभिन्न हिस्सों में उत्तर-पूर्व के लोगों पर हमले भी हुए हैं।

(10) महिलाओं पर हमलों के पैमाने और प्रकृति में चौंकानेवाली बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं, युवतियों तथा बच्चों के खिलाफ हमले बेहिसाब बढ़े हैं। पितृसत्तावादी तथा बाजारवादी मूल्यों के चलते महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है।

(11) इस दौर में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बढ़ती हुई एकजुट कार्रवाइयां हुई हैं, जो 2013 की फरवरी की दो दिन की ऐतिहासिक आम हड़ताल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची हैं। श्रम कानूनों के कमजोर किए जाने के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का एकजुट संघर्ष जारी है।

(12) इस दौर में पश्चिम बंगाल में सी पी आइ (एम) तथा वामपंथ के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार के हमले लगातार जारी रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सी पी आइ (एम) तथा वामपंथ को गंभीर चुनावी धक्के लगे हैं, जो प्राथमिकता के आधार पर सी पी आइ (एम) तथा वामपंथ को मजबूत करने की जरूरत को रेखांकित करते हैं।

आर्थिक परिस्थिति

2.4 पिछले दो वर्षों ने इसी की पुष्टि की है कि नवउदारवादी विकास पथ गंभीर संकट के दौर में प्रवेश कर गया है और शुरू में जो इस तरह की उम्मीदें लगायी जा रही थीं कि भारत जैसे देश विश्व पूंजीवाद के लंबी अवधि के संकट से बच निकलेंगे, झूठी साबित हुई हैं।

2.5 इस संकट की सबसे प्रमुख निशानी है, आर्थिक वृद्धि दर का धीमा पड़ना, जबकि विश्व संकट के फौरन बाद के दौर को छोड़कर, करीब एक दशक तक यह दर बहुत ऊपर बनी रही थी। मंदी के चिन्ह तो 2011-12 के उत्तरार्द्ध से ही सामने आने शुरू हो गए थे। 2012-13 तथा 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद की सालाना वृद्धि दर 5 फीसद से नीचे रही थी और 2014-15 की पहली दो तिमाहियों के आंकड़े दिखाते हैं कि इस साल इसमें बहुत मामूली बढ़ोतरी ही होने जा रही है। हालांकि वृद्धि दर में यह मंदी अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में देखने को मिली है, जिसमें अनेक सेवाएं तथा निर्माण का क्षेत्र भी शामिल है, फिर भी सबसे बुरी मार

औद्योगिक क्षेत्र पर ही पड़ी है। विनिर्माण में वृद्धि दर 2011 की जुलाई के बाद से, चालीस महीने से ज्यादा से शून्य के करीब बनी रही है।

2.6 यूपीए सरकार ने इस स्थिति का सामना बहुत सारे ऐसे कदमों से करने की कोशिश की, जो विदेशी पूंजी के हित साधते हैं और भारतीय बड़ी पूंजी को खुश करते हैं। विदेशी कंपनियों तथा भारतीय बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए और ज्यादा कर रियायतें दी गयीं तथा कर प्रावधानों में ढील दी गयी। सरकार ने यह फैसला लिया कि बहुब्रांड खुदरा व्यापार में 51 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत दी जाए। बैंकिंग नियमों में संशोधन का कानून बनाकर, विदेशी बैंकों को भारतीय बैंकों में अपने शेयरों पर 26 फीसद तक मताधिकार की इजाजत दे दी गयी, जबकि पहले इसकी अधिकतम सीमा 10 फीसद थी। औद्योगिक घरानों के लिए निजी बैंक चलाने का रास्ता खोल दिया गया। पेंशन कानून बनाकर, पेंशन फंडों का निजीकरण कर दिया गया और पेंशन फंडों में 26 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत दे दी गयी। राष्ट्रीय दवा नीति की घोषणा की गयी, जिसमें दवाओं के मूल्य के नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था का प्रावधान था, जो बेहिसाब मुनाफे बनाने में बड़ी दवा कंपनियों की मदद करेगी, जिसमें बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां भी शामिल हैं।

2.7 यूपीए के राज में पूंजी खर्च के साथ ही साथ, खर्चों पर नियंत्रण की जो रणनीति अपनायी गयी थी, उसकी मार कृषि तथा ग्रामीण विकास, उर्वरक व खाद्य सब्सीडी और सामाजिक क्षेत्र पर खर्चे जैसे उन्हीं क्षेत्रों पर पड़ रही थी, जिनका आम आदमी के जीवन पर ज्यादा असर पड़ता है। वास्तविक मूल्य के पहलू से इन मदों में यूपीए-द्वितीय के पांच सालों में किया गया खर्चा, यूपीए-प्रथम के अंतिम वर्ष के खर्चे के मुकाबले घटकर ही था। मोदी सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम पर खर्चे में, स्वास्थ्य बजट में तथा अन्य कल्याणकारी खर्चों में कटौती करने और विनिवेश कार्यक्रम को तेज करने जैसे जो कदम उठाए हैं, साफ तौर पर यही दिखाते हैं आने वाले दिनों में वही सब और ज्यादा किए जाने की ही उम्मीद की जानी चाहिए।

2.8 मोदी सरकार आक्रामक तरीके से नवउदारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। भाजपा की सरकार ने रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने का एलान किया है तथा प्रतिरक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। उसने एक अध्यादेश के जरिए, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 फीसद कर दी है और अचल संपत्ति के क्षेत्र में

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील दे दी है। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को बैठा दिया गया है। यह प्रधानमंत्री के अधीन एक निकाय होगा और राज्यों के लिए वित्तीय आवंटनों को और केंद्रीयकृत कर दिया जाएगा।

2.9 2014–15 के संघीय बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों में 43,425 करोड़ रु0 के विनिवेश का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने कोयला खदान ब्लाकों के आवंटन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है और इसके साथ ही कोयला राष्ट्रीयकरण कानून में संशोधन कर व्यापारिक निजी खनन की इजाजत दे दी है, जो कोयला खनन के विराष्ट्रीयकरण की ओर ले जाता है। सरकार ने डीजल के दाम को नियंत्रणमुक्त कर दिया है। उसने वनों के इलाके में खनन व बिजली की परियोजनाओं को बड़ी संख्या में पर्यावरण अनुमति दे दी है। इसका आदिवासियों के अधिकारों पर और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। मोदी सरकार आने के बाद भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी ही बनी हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के 2.5 फीसद से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। मानसून सामान्य से कम रहने के चलते, 2014–15 में कृषि उत्पादन में गिरावट की ही अपेक्षा है।

2.10 मुद्रास्फीति की प्रक्रिया बहुत हद तक खाने-पीने की चीजों में केंद्रित रही है। खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी का रुझान करीब एक दशक से छाया रहा है और इसके चलते इस दौर में खाने-पीने की ज्यादातर चीजों की कीमतें दोगुनी हो गयी हैं। जहां वृद्धि दर मामूली बनी रही है, मुद्रास्फीति की दर आम आदमी के लिए बेतुके तरीके से ऊंची बनी रही है। हालांकि सरकार थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट की ओर इशारे कर रही है, खाने-पीने की वस्तुओं के मामले में मुद्रास्फीति, 2014–15 में 8.63 फीसद के ऊंचे स्तर पर ही बनी रही है। यह इसके बावजूद है कि कच्चे तेल के आयात के दाम में भारी गिरावट हुई है, जिससे ऊर्जा के दाम में गिरावट की तथा मुद्रास्फीति की दर घटने की उम्मीद की जाती है। तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम में भारी गिरावट हुई है और 2014 के जून के बाद से ये दाम, 55 फीसद घट गए हैं। लेकिन, मोदी सरकार ने इसी बीच तेल के आयातों पर उत्पाद शुल्क में चार बार बढ़ोतरी की है और इस तरह पैट्रोल तथा डीजल के दाम में कमी के रूप में जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंचने दिया है।

2.11 पिछले तीन वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी है। रोजगार की वृद्धि दर एक फीसद से

कम रही है, जिसके चलते शहरी तथा ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारों की कतारें और लंबी हो गयी हैं। 15 से 29 वर्ष तक के आयु वर्ग के मामले में, जिसमें 33 करोड़ लोग आते हैं, बेरोजगारी की दर 13.3 फीसद है। उद्योग तथा अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ने से इंजीनियरों तथा तकनीकीकर्मियों के बीच बेरोजगारी पैदा हो रही है। महिला मजदूरों की संख्या में भारी गिरावट हुई है। जो रोजगार उपलब्ध भी हैं, कम मजदूरीवाले हैं और रोजगार की कोई सुरक्षा भी नहीं है। यह नवउदारवादी निजाम में एक आम बात है।

2.12 चूंकि वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए सार्वजनिक खर्चों व निवेशों का उपयोग करने की नीति नहीं अपनायी गयी है, निजी निवेशों को आकर्षित करने तथा मुनाफों को उत्प्रेरित करने के दूसरे कदमों को लादा जा रहा है। इसके मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं। अ) श्रम कानूनों में बदलावों के जरिए, जिससे 'लचीलापन' बढ़ाया जा सके, श्रम के मुकाबले में पूंजी की स्थिति और मजबूत करना। आ) किसानों तथा आदिवासियों की कीमत पर, बड़ी पूंजी के लिए अचल संपत्ति, ढांचागत क्षेत्र, खनन व औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सस्ती जमीन हासिल करना आसान बनाना, जिसके लिए अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण कानूनों में संशोधन किए गए हैं। इ) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों व गतिविधियों के निजीकरण के जरिए, बढ़ते पैमाने पर राष्ट्रीय संसाधनों का कार्पोरेट घरानों के हवाले किया जाना। यही प्रक्रिया है जिसके चलते यूपीए के निजाम में हर तरफ भ्रष्टाचार फूट पड़ा था। ई) पर्यावरण मानकों को नीचा करना ताकि और ज्यादा परियोजनाओं को अनुमोदन दिलाया जा सके। उ) कर रियायतें तथा ऋण माफियां देना ताकि जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए संसाधन निकालना और मुश्किल हो जाए। ऊ) सामाजिक क्षेत्र पर खर्चों में उल्लेखनीय कटौतियां करना।

2.13 मौजूदा संकट पर भारतीय शासन की प्रतिक्रिया पूंजीपति वर्ग के क्षुद्र वर्गीय परिप्रेक्ष्य को ही प्रतिबिंबित करती है और सारत: उसी प्रक्रिया को दोहराने की कोशिश है, जिसने संकट पैदा किया है। दूसरे शब्दों में यह नवउदारवादी ढांचे में ही समाधान निकालने की कोशिश है, जो पहले ही मौजूद बेरोजगारी तथा आय के संकट को बढ़ाने के जरिए ही काम कर सकता है। यह अपने आप में एक ओर सत्ताधारी वर्ग और दूसरी ओर मेहनतकश जनता, जिसमें मजदूर वर्ग तथा किसान दोनों शामिल हैं, के हितों के बीच

के अंतर्विरोध को बढ़ा रहा है। जनता के खिलाफ यह चौतरफा हमला, मौजूदा परिस्थिति संयोग में बढ़ती तानाशाही को शासक वर्ग की जरूरत बना देता है।

कृषि क्षेत्र में परिस्थितियां

2.14 पिछले तीन साल में ग्रामीण भारत में कृषि की परिस्थितियां गरीब व मंझले किसानों तथा ग्रामीण खेतमजदूरों की विशाल संख्या के लिए और भी बिगड़ गयी हैं। कृषि उत्पाद में दीर्घावधि मंदी बनी रही है और खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता जहां की तहां रुकी रही है। कृषि में पूंजी निर्माण में सार्वजनिक निवेश, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में गिरा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल आदि अनेक राज्यों में किसानों की आत्महत्याएं जारी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2013 में कृषि में लगे 11,772 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। खेती पर इस तरह के दबाव का मुख्य कारण है खेती का और खासतौर पर छोटे तथा सीमांत किसानों की खेती का बढ़ते पैमाने पर अलाभकर होते जाना। छोटी किसानी की अर्थव्यवस्था का यह संकट, जिसकी पहचान खेती में लगने वाली सामग्री की बढ़ती कीमतों तथा कृषि उत्पाद की कीमतों में उस अनुपात में बढ़ोतरी न होने से होती है, और बढ़ गया है।

2.15 एक ओर 2012 के बाद से, सरकार की नीतियों के चलते खेती में लगने वाली सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बिजली तथा ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। सार्वजनिक कृषि शोध का दर्जा घटाए जाने के चलते बीज के उत्पादन तथा वितरण में, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा घरेलू कार्पोरेटों की बाजार की शक्ति बढ़ी है। खेती की लागत सामग्री पर कार्पोरेटों का नियंत्रण बढ़ रहा है। दूसरी ओर, खेती की तरह-तरह की लागत सामग्रियों की कीमतों में तो तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कृषि उत्पाद की कीमतों में उसी अनुपात में बढ़ोतरी के जरिए, लागत की उक्त बढ़ोतरी की भरपाई नहीं की गयी है। वास्तव में चाय, रबर, काली मिर्च, नारियल, कपास, तुअर, चना तथा प्याज के दाम या तो जहां के तहां रुके रहे हैं या फिर गिरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि मालों के दाम में गिरावट का किसानों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इस तरह की परिस्थितियों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मजबूत किया जाना राहत का एक रूप हो सकता था। लेकिन, नयी सरकार तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही नष्ट करने पर और खलिहान से खरीद के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों तथा खुदरा

क्षेत्र की भीमकाय कंपनियों को आमंत्रित करने पर तुली हुई है। गन्ना उत्पादक किसान, चीनी मिलों से करीब 110 अरब रुपये के बकाया का भुगतान कराने में शासन की विफलता की मार झेल रहे हैं।

2.16 कृषि ऋणों में बढ़ोतरी बहुत ही असंतुलित रही है और बहुराष्ट्रीय निगमों, कृषि-व्यापारिक घरानों तथा बड़े किसानों के पक्ष में झुकी रही है। छोटे तथा सीमांत किसानों को औपचारिक ऋण व्यवस्था से बाहर धकेला जा रहा है, जिसने उन्हें सूदखोरों की शरण लेने के लिए मजबूर किया है। किसानों के बीच ऋणग्रस्तता बढ़ रही है।

2.17 सहकारी ऋण समितियों के संबंध में नयी नीतियां भारत की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारिताओं की नींव ही खोदने की कोशिश कर रही हैं। इन सहकारिताओं को, व्यावसायिक बैंकों के लिए, ''बैंकिंग करोस्पोंडेंटों'' में तब्दील किया जा रहा है, जमा-राशियां स्वीकार करने से रोका जा रहा है और उन्हें व्यापारिक बैंकों तथा उनके ग्राहकों के बीच, बिचौलिये बनाकर छोड़ा जा रहा है।

2.18 उदारीकरण के तहत देहात में आए बदलावों का लाभ भूस्वामियों तथा बड़े पूंजीवादी किसानों को मिला है। दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए, जिनमें कृषि तथा गैर-कृषि, दोनों ही तरह के मजदूर शामिल हैं, मजदूरी की कुल दरें नीची बनी रही हैं। मजदूरी की इन दरों की पहचान, उनमें बहुत भारी क्षेत्रीय भिन्नताओं तथा बहुत भारी लैंगिक भेदभाव से होती है। इसके अलावा ग्रामीण मजदूरों के लिए और खासतौर पर महिला मजदूरों के लिए काम के दिनों की संख्या, दयनीय तरीके से कम है। प्रवासी मजदूरों की दशा बहुत ही खराब है और इन प्रवासी मजदूरों के पीछे गांवों में छूट जाने वाले परिवारों की भी दशा खराब है।

2.19 भाजपा की सरकार ने, पिछली संसद द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण कानून में अलोकतांत्रित तरीके से एक अध्यादेश के जरिए संशोधन किया है ताकि कार्पोरेटों तथा भूमाफिया द्वारा मुनाफाखोरी तथा अचल संपत्ति में सट्टाबाजारी को बढ़ावा दिया जा सके। अध्यादेश में किसानों की तथा भूमि पर निर्भर लाखों लोगों की जायज चिंताओं को अनदेखा कर दिया गया है। वास्तव में इसके जरिए, 1894 के औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण कानून के सबसे दमनकारी तत्वों को बहाल कर दिया गया है।

असमानताएं बढ़ीं

2.20 समीक्ष्य अवधि में नवउदारवादी नीतियों के चलते असमानताएं बढ़ी हैं। फोर्ब्स की 2014 सूची के अनुसार, भारत के 100 सबसे धनी, सब के सब डालर में अरबपति हैं (1 अरब डालर, 6,200 करोड़ रु0 के बराबर होता है)। डालर अरबपतियों की संख्या 2011 की कुल 55 की संख्या के मुकाबले, 45 की बढ़ोतरी को दिखाती है। इन सौ अरबपतियों की कुल संपदा 346 अरब डालर बैठती है। देश के सभी परिवारों की सकल संपदा में सबसे धनी एक फीसद परिवारों का हिस्सा जो सन 2000 में 36.8 फीसद था, जबर्दस्त बढ़ोतरी के साथ 2014 में 49 फीसद पर पहुंच चुका था। (क्रेडिट सुइस की, 'ग्लोबल वैल्थ रिपोर्ट')

2.21 एक ओर यह अश्लील अमीरी है और दूसरी ओर भारत के ग्रामीण परिवारों में से 80 फीसद से ज्यादा 2011-12 में, 50 रु0 या उससे भी कम के दैनिक प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता खर्चे पर ही गुजारा कर रहे थे। यही बात कुल शहरी परिवारों के 45 फीसद के बारे में भी सच थी। खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 2012 में 164 किलोग्राम प्रति वर्ष ही थी, जोकि 1991 के आंकड़े से कम है, जब यही उपलब्धता 186 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति, प्रतिवर्ष की थी।

2.22 बड़े पूंजीपतियों की बढ़ती संपदा तथा मुनाफे, श्रम के तीव्रीकृत शोषण का ही परिणाम हैं। फैक्ट्री क्षेत्र में शुद्ध मूल्य संवर्द्धन में मजदूरी का हिस्सा 2011-12 में घटकर 11.9 फीसद ही रह गया था, जबकि 1990-91 में यही हिस्सा, 25.6 फीसद था।

2.23 कार्पोरेट क्षेत्र और धनी तबकों को शासन की दानवीरता का लाभ मिला है। 2008-09 से 2012-13 के बीच, चार वर्ष की अवधि में शासन द्वारा त्याग दिया गया राजस्व 23.84 लाख करोड़ रु0 का था।

मजदूरों की दशा

2.24 नवउदारवादी निजाम की पहचान मजदूरों के रोजगार की प्रकृति में ऐसे बदलावों से होती है, जो तीव्रीकृत शोषण को सुगम बनाते हैं। संगठित क्षेत्र में प्रति मजदूर औसत वास्तविक मजदूरी में गिरावट हुई है। 1990-91 में यह मजदूरी 108 रु0 41 पैसा थी, जो 2010-11 तक घटकर 103 रु0 76 पैसा रह गयी। ठेकाकरण, अस्थायीकरण तथा आउटसोर्सिंग ऐसे

साधन हैं, जिनसे श्रम का शोषण तेज किया जा रहा है। कुल संगठित रोजगार में ठेका मजदूरों का हिस्सा जो 1995-96 में 10.54 फीसद था, 2009-10 तक बढ़कर 25.7 फीसद हो चुका था। घर से काम करने वाले मजदूरों को, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं और जिनके लिए कंपनियां काम आउटसोर्स करती हैं, पीस रेट मजदूरी के रूप में बहुत ही थोड़ी मजदूरी दी जाती है। सरकार की विभिन्न योजनाओं में काम कर रहे ''स्कीम'' मजदूरों को, मानदेय के रूप में नाममात्र की राशि दी जाती है और सभी वैधानिक लाभों से वंचित रखा जाता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में एक बड़ा हिस्सा प्रवासी मजदूरों का है, जिनकी दशा और भी खराब है। उन्हें दिहाड़ी मजदूरों के रूप में दयनीय हालात में काम करना होता है और कोई सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं होती है।

भ्रष्टाचार और काला धन

2.25 यूपीए-द्वितीय के कार्यकाल में बेनकाब हुए भ्रष्टाचार घोटालों की बाढ़ वाकई अभूतपूर्व थी। उसने यह दिखाया कि किस तरह नवउदारवादी निजाम में, प्राकृतिक संसाधनों की लूट को आसान बनाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया गया है। इससे पहले, 2-जी स्पैक्ट्रम प्रकरण ने बड़ी पूंजी-राजनीतिज्ञ-नौकरशाह गठजोड़ को उजागर किया था। आगे चलकर, 2012 में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की रिपोर्ट ने दिखाया कि किस तरह कोयला ब्लाकों के आवंटन से निजी कंपनियों ने 1.86 लाख करोड़ रु0 अपनी तिजोरियों में डाल लिए थे। इसके बाद ऑगस्टा-वेस्टलैंड हैलीकोप्टर सौदे का घोटाला और रेल मंत्रालय घूसखोरी प्रकरण सामने आए। राज्यों में भी भ्रष्टाचार घोटालों की बाढ़ देखने को मिली है, जैसे पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाला, ओडिशा में चिटफंड घोटाले और केरल में सोलर पैनल घोटाला।

2.26 कार्पोरेट मीडिया तथा आम धारणा के स्तर पर भी, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए भ्रष्ट राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों को ही जिम्मेदार माना जा रहा था और भ्रष्टाचार के स्रोत, नवउदारवादी निजाम की तरफ इशारा ही नहीं किया जा रहा था। यही है जिसने बड़े व्यापारिक घरानों के लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेना संभव बनाया था। 2013 में पारित लोकपाल कानून में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत परिभाषित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच-पड़ताल के लिए एक संस्था का गठन किया गया है। बहरहाल, सी पी आइ (एम) तथा वामपंथ के लिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में अनिवार्य

रूप से नवउदारवादी निजाम तथा भ्रष्ट गठजोड़ को ध्वस्त करना भी शामिल है।

2.27 सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि आजादी के बाद से अवैध रूप से देश से बाहर गए धन के चलते भारत को 20.92 करोड़ रु0 का नुकसान हुआ है। इसमें से 11.28 करोड़ रु0 तो 2008 से 2010 के बीच ही गए हैं। बहरहाल, अवैध रूप से दूसरे देशों में जमा कर के रखे गए इस धन को वापस लाने के लिए यूपीए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सत्ता में आने के बाद सौ दिन के अंदर-अंदर विदेश से काला धन वापस लाने का वादा करने के बाद, मोदी सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। न तो भाजपा और न कांग्रेस की ओर से इसकी कोई चर्चा हो रही है कि खुद देश के अंदर काले धन का उत्पादन रोकने के लिए और ऐसा अवैध धन निकलवाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

हिंदुत्व परियोजना: धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के लिए खतरा

2.28 लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत से पहले आर एस एस तथा उसके मोर्चा संगठनों द्वारा अपने सांप्रदायिक एजेंडा को लेकर सुव्यवस्थित तरीके से अभियान चलाया गया था। गोहत्या, मुस्लिम युवाओं द्वारा हिंदू लड़कियों को बरगलाए जाने के आरोप, बांग्लादेशी घुसपैठ तथा वोट बैंक की खातिर मुसलमानों का तुष्टीकरण किए जाने का आम प्रचार, इन सभी का इस्तेमाल कर सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जा रहे थे और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को उकसाया जा रहा था। 2013 के साल में सांप्रदायिक घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी और इनमें से ज्यादातर घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही हुई थीं। 2013 के सितंबर में मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण पैदा करने में कामयाब रही। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में भी सांप्रदायिक घटनाएं हुईं। चुनाव के नतीजे आने और मोदी सरकार बनने के बाद विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक घटनाएं होना जारी है। इन घटनाओं का मकसद अल्पसंख्यकों को यह संदेश देना है कि भाजपा के राज में उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा।

2.29 भाजपा के सत्ता में आने और आर एस एस की कार्ययोजना के लागू किए जाने से, हालात में गुणात्मक बदलाव आया है। आर एस एस और अति-महत्वपूर्ण मंत्रालयों में बैठे मंत्रियों के बीच, घनिष्ठ तालमेल कायम किया गया है। इसे सुगम बनाने के लिए आर एस एस ने छः समूह गठित किए

हैं। शिक्षा व्यवस्था सबसे बढ़कर निशाने पर है। नयी शिक्षा नीति तैयार की जा रही है, जिसके जरिए पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में बदलाव कर, सांप्रदायिक अंतर्वस्तु को लाया जाएगा। इतिहास का पुनर्लेखन किया जाएगा और अन्य भारतीय भाषाओं की कीमत पर संस्कृत को आगे बढ़ाया जा रहा होगा। उच्च शिक्षा तथा शोध के शीर्ष नीति निर्धारक निकायों के प्रमुखों के रूप में ऐसे लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जो इस काम को अंजाम देंगे। प्रधानमंत्री से लगाकर नीचे तक पोंगापंथी मूल्यों को फैलाया जा रहा है और वैज्ञानिक सोच को कमजोर किया जा रहा है।

2.30 विघटनकारी हिंदुत्व परियोजना को आगे बढ़ाने की चौतरफा कोशिश सामने आ रही है, जिससे हमारे गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष-जनतांत्रिक आधार के लिए ही खतरा पैदा हो रहा है। भाजपा के नेताओं व सांसदों के हिंदुत्व के विचारों को स्वीकार न करने वालों को धमकाने वाले बयान; नाथूराम गोडसे का महिमामंडन; मुसलमानों तथा ईसाइयों का हिंदू धर्म में ''पुनर्धर्मांतरण''; अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मांग; ये सभी आर एस एस-संचालित योजना के हिस्से हैं। हिंदुत्व, परंपरा के नाम पर वर्तमान जातिवादी ढांचे की हिमायत करता है तथा उसे मजबूत करता है। हिंदुत्व, प्रतिगामी पितृसत्तात्मक धारणाओं की भी वकालत करता है, जो महिलाओं को सिर्फ समुदाय तथा परिवार की ''इज्जत'' के कोष के रूप में देखती हैं और उनसे तथाकथित परंपरा को कायम रखने के लिए, अधीनता का दर्जा स्वीकार करने का तकाजा करती हैं। इस सिलसिले में ताजातरीन हमला है हिंदू औरतों के लिए यह फरमान कि और ज्यादा बच्चे पैदा करें।

2.31 सरकारी संरक्षण हासिल हो जाने के बाद, अब जमीनी स्तर पर आर एस एस के संगठनों के संजाल को सरकार से अनुमोदन तथा पैसे की मदद मिल रही होगी। आर एस एस के संगठन अपनी सर्व-हिंदुत्व विचारधारा तथा व्यवस्था में दलितों तथा आदिवासियों को खींचने पर खासतौर पर अपने प्रयासों को केंद्रित कर रहे हैं।

सांप्रदायिकता से लड़ने का रास्ता

2.32 हिंदुत्ववादी ताकतों तथा सांप्रदायिकता के अन्य रूपों के खिलाफ संघर्ष को मेहनतकश जनता पर नवउदारवादी नीतियों तथा उनके दुष्प्रभावों के खिलाफ संघर्ष के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अपनी रोजी-रोटी की रक्षा के लिए और मोदी सरकार द्वारा तथा भाजपायी राज्य सरकारों द्वारा थोपे जा रहे बोझ के

खिलाफ जनता को गोलबंद करने से ही, आरएसएस के नेतृत्ववाली सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अभियान, जन-प्रभाव हासिल कर सकता है।

2.33 हिंदुत्ववादी ताकतों के धावे तथा अल्पसंख्यकों पर हमलों से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अतिवादी ताकतों के उभार में मददगार हैं। इसलिए, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का मुकाबला करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वह बहुसंख्यक सांप्रदायिकता की ताकतों की ही मदद करती है।

2.34 सांप्रदायिक ताकतों से आ रहे खतरे को देखते हुए हमें धर्मनिरपेक्ष तथा जनतांत्रिक ताकतों की व्यापकतम गोलबंदी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सांप्रदायिकता के खिलाफ एक व्यापकतर एकजुट आंदोलन के लिए संयुक्त मंचों का निर्माण जरूरी है।

2.35 आर एस एस-भाजपा जोड़ी के खिलाफ संघर्ष की कार्यनीति को सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में भी ठोस रूप देना होगा। इन्हीं क्षेत्रों में सांप्रदायिक विचारधारा तथा मूल्यों को फैलाया जाता है और वे प्रभाव हासिल करते हैं। राजनीतिक संघर्ष के साथ ही पार्टी तथा जनसंगठनों को निम्नलिखित को हाथ में लेना चाहिए:

(1) हिंदुत्व तथा सांप्रदायिकता के अन्य रूपों की प्रतिक्रियावादी तथा विभाजनकारी प्रकृति को बेनकाब करने के अभियान में उपयोग के लिए लोकप्रिय शैली में विचारधारात्मक तथा राजनीतिक सामग्री तैयार की जानी चाहिए। पार्टी द्वारा संचालित बौद्धिक संसाधनों व शोध केंद्रों को, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ विचारधारात्मक संघर्ष के लिए बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों तथा सांस्कृतिक हस्तियों को गोलबंद करने के लिए लगाया जाना चाहिए।

(2) शिक्षा के क्षेत्र में प्री-स्कूल तथा स्कूल स्तर पर, शिक्षकों व सामाजिक संगठनों की मदद से पहलें की जानी चाहिए।

(3) मजदूर वर्ग के बीच तथा मजदूर वर्ग के रिहाइशी इलाकों में धर्मनिरपेक्ष तथा वैज्ञानिक नजरिए के प्रसार के लिए, पार्टी तथा ट्रेड यूनियनों द्वारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(4) सांप्रदायिक ताकतों द्वारा फैलाये जा रहे जहरीले, जातिवादी तथा पोंगापंथी मूल्यों का मुकाबला करने के लिए, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों का विकास किया जाए। इस काम के लिए जन विज्ञान आंदोलन को लगाया जाना चाहिए।

(5) आदिवासी इलाकों में तथा दलितों के बीच सांगठनिक काम का विकास किया जाए ताकि आर एस एस के संगठनों की चहुंमुखी गतिविधियों की काट की जा सके।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत

2.36 हिंदुत्ववादी हमला खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाता है। पुनर्धर्मांतरण अभियान और तथाकथित लव-जेहाद (विरोधी) अभियान, अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा तथा डर पैदा कर रहे हैं। भाजपा के केंद्र में सत्ता में आने के साथ मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक वंचितता के सच्चे प्रश्न को और सच्चर रिपोर्ट की सिफारिशों को एजेंडा से ही परे खिसका दिया गया है। इन हालात में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना और अल्पसंख्यकों के शैक्षणिव व आर्थिक विकास के लिए विशेष कदम उठाए जाने की मांग करना, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।

जम्मू-कश्मीर

2.37 यूपीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक प्रश्न पर सार्थक रूप से कुछ भी नहीं किया था। जम्मू-कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई राजनीतिक संवाद नहीं किया गया। उल्टे जम्मू और घाटी के बीच सांप्रदायिक विभाजन ही बढ़ गया। भाजपा के केंद्र में सरकार में आने से तथा राज्य सरकार में उसके संभावित प्रवेश से, यह विभाजन और तेज हो रहा है। सी पी आइ (एम) अपना यह बुनियादी रुख दोहराती है कि राज्य के लिए अधिकतम स्वायत्तता और इसके साथ ही तीनों क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता के प्रावधान पर आधारित राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए।

विदेश नीति की दिशा

2.38 1990 के दशक में उदारीकरण के आने के साथ ही अमरीकापरस्त विदेश नीति की दिशा में बढ़ना शुरू हो गया था। यूपीए सरकार ने अमरीका के साथ जो रणनीतिक गठजोड़ कायम किया, उसकी शुरूआत वाजपेयी

सरकार ने की थी। यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार का इरादा इसी रास्ते पर आगे जाने का है। 2014 के सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी की वाशिंगटन की यात्रा के दौरान, (2015 की जनवरी से) अगले दस साल के लिए भारत-अमरीका रक्षा रूपरेखा समझौते के पुनर्नवीकरण का एलान किया गया था। मोदी सरकार जापान तथा आस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक व सैन्य रिश्ते मजबूत कर रही है और इनमें बाद वाले देश के साथ उसने एक सुरक्षा सहयोग रूपरेखा समझौते पर दस्तखत किए हैं। ओबामा की 2015 की जनवरी की यात्रा के दौरान एशिया-प्रशांत तथा हिंद महासागर क्षेत्र पर जो संयुक्त विजन वक्तव्य जारी किया गया है, पहली बार साफ तौर पर भारत की 'पूर्व की ओर कार्रवाई' की नीति को, एशिया के लिए अमरीका की धुरी के साथ जोड़ता है, जोकि चीन पर अंकुश लगाने के लिए है। इस तरह के रुख का परिणाम यह होगा कि अमरीका, भारत, जापान तथा आस्ट्रेलिया का एक चतुष्कोणीय सुरक्षा गठजोड़ उभरकर सामने आएगा।

2.39 भाजपा की सरकार इस्राइल के साथ अपना सुरक्षा तथा रणनीतिक गठजोड़ बढ़ा रही है। पाकिस्तान के साथ पिछले साल विदेश मंत्री स्तर की बातचीत रद्द करने के बाद से भाजपा सरकार, उसके प्रति टकरावावादी रुख अपना रही है। जहां रूस के साथ संबंधों को पोसा जा रहा है, मोदी सरकार को चीन के साथ संबंध सुधारने तथा उन्हें मजबूत करने के रास्ते में अपने विचारधारात्मक झुकावों को नहीं आने देना चाहिए।

2.40 पार्टी को अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ के खिलाफ लगातार अभियान चलाना होगा और एक स्वतंत्र विदेश नीति की वकालत करनी होगी क्योंकि वही सही तरीके से हमारे देश के हित पूरे कर सकती है।

राजसत्ता और नवउदारवादी निजाम

2.41 नवउदारवादी नजरिया शासन (राज्य) और उसकी संस्थाओं को कमजोर कर रहा है तथा प्रभावित कर रहा है। राज्य, बढ़ते पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने तथा पूंजी का संचय करने के लिए, बड़ी पूंजी के हाथों में औजार की तरह काम कर रहा है। राज्य, बाजार की ताकतों के लिए सुगमताकारक की तरह और उसके रास्ते में जो भी बाधाएं आएं उन्हें दूर करने के लिए काम करता है। इसके साथ ही, कल्याणकारी कदम मुहैया कराने वाले के रूप में राज्य की भूमिका पर हमला हो रहा है। नवउदारवाद के असर के चलते, कारोबार और राजनीति में बढ़ता हुआ

गठजोड़ सामने आ रहा है। बड़ा पैसा चुनावी प्रणाली में समा गया है। राजनीति तथा कारोबार के अंतर्ग्रथन ने जनतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है। इसके चलते, संसदीय जनतंत्र कमजोर हो रहा है। बुनियादी आर्थिक नीतियां, संसद तथा विधानसभाओं से परे तय हो रही हैं। मोदी सरकार महत्वपूर्ण नीतिगत कदम थोपने के लिए बढ़ते पैमाने पर अध्यादेशों का सहारा ले रही है और इस तरह संसदीय जनतंत्र को कमजोर कर रही है।

2.42 राजकोषीय हस्तांतरणों पर तथा विश्व बैंक से लिए गए ऋणों के जरिए थोपी गयी शर्तों के जरिए, राज्यों (प्रदेशों) को निजीकरण, उपयोक्ता शुल्क लगाने तथा कृषि मंडियों का निजीकरण करने की नीतियां लागू करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे हालात में ही भाजपा के राज में, शासन की संस्थाओं का संप्रदायीकरण करने की कोशिशें की जा रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सब एक तानाशाहीपूर्ण निजाम कायम किए जाने के इशारे हैं।

चुनाव सुधार के लिए संघर्ष

2.43 बड़े पैसे द्वारा जनतंत्र का कमजोर किया जाना और 'जो ज्यादा पाए सब ले जाए' (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) चुनाव प्रणाली की विकृतियां, सब बुनियादी चुनाव सुधारों के ही महत्व को रेखांकित करते हैं। पार्टी को, एक आंशिक सूची व्यवस्था के साथ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाए जाने के लिए अभियान चलाना चाहिए। इसके साथ ही, सामग्री के रूप में शासन द्वारा चुनाव की फंडिंग की जानी चाहिए और चुनावों मे अवैध रूप से पैसा खर्च किए जाने पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। यह जरूरी है कि पार्टी द्वारा किए जाने वाले खर्च को, चुनाव में उम्मीदवार के खर्च में शामिल किया जाए।

शासन द्वारा दमन, जनतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश

2.44 बढ़ते तानाशाहीपूर्ण रुझानों की अभिव्यक्ति, जनतांत्रिक अधिकारों के गंभीर अतिक्रमणों और नागरिक स्वाधीनताओं पर हमलों में हो रही है। विरोध की आवाज उठाने, प्रदर्शन व जनसभाएं करने के अधिकारों पर, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगाए जा रहे हैं। इस तरह के अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

2.45 दमनकारी कानूनों के जरिए राजकीय दमन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर तथा मणिपुर में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियां कानून (अफस्पा) का नतीजा यह हुआ है कि सुरक्षा बलों ने बेरोक-टोक नागरिकों की हत्याएं की हैं। शासकीय मशीनरी द्वारा आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून (यूएपीए) का भी सहारा लिया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में ऐसी अनगिनत मिसालें सामने आयी हैं, जहां लंबे अर्से तक जेलों में बंद रहे मुस्लिम युवाओं को अदालतों ने सारे आरोपों से बरी कर दिया है। भारतीय दंड संहिता के कठोर प्रावधानों का जन-आंदोलनों के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने वालों के खिलाफ अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कानून की धारा 66-ए का इस्तेमाल कर इंटरनेट तथा सोशल मीडिया में असहमति की आवाजों को दबाया जा रहा है। बढ़ते पैमाने पर पुलिस का सत्ताधारी पार्टी के हित साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ जगहों पर पुलिस, सत्ताधारी राजनीतिज्ञों तथा माफिया गिरोहों का गठजोड़ चल रहा है। एक खतरनाक रुझान जो उभरकर सामने आ रहा है, भाजपा-शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के हिंदुत्ववादी ताकतों के अवैध फरमान पूरे करने के लिए, पुलिस का इस्तेमाल है।

2.46 यह सब जनतांत्रिक अधिकारों व नागरिक स्वाधीनताओं की रक्षा करने के लिए, तमाम जनतांत्रिक शक्तियों तथा नागरिक समूहों को गोलबंद करने के महत्व को रेखांकित करता है।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति

भाजपा और कांग्रेस

2.47 आज की परिस्थितियों में सत्ताधारी वर्ग की दो प्रमुख पार्टियों की सापेक्ष शक्ति में उल्लेखनीय बदलाव आ चुका है। कांग्रेस की कीमत पर भाजपा ताकतवर हुई है। वह लोकसभा चुनाव में सिर्फ 31 फीसद वोट हासिल कर, 282 सीटें जीत गयी है। बहरहाल, वह मध्य वर्ग व युवाओं के बीच और ग्रामीण इलाकों में अन्य पिछड़े वर्गों के बीच से नया समर्थन जुटाने में कामयाब रही है। भाजपा के नये इलाकों में अपने पांव फैलाने का पता हरियाणा, महाराष्ट्र तथा झारखंड के विधानसभाई चुनावों में उसकी जीत से

चलता है। लगातार दो संसदीय चुनावों में हार के बाद से भाजपा अस्त-व्यस्त हो रही थी। अंततः आर एस एस के ही हस्तक्षेप ने पार्टी से नये नेतृत्व का चुनाव कराया। इसका एक उल्लेखनीय नतीजा यह हुआ है कि पार्टी पर आर एस एस का नियंत्रण तथा चंगुल कसा है।

2.48 कांग्रेस पार्टी की दीर्घावधि गिरावट, जिसे 2004 तथा 2009 के चुनावों में यूपीए की जीत ने ढांप दिया था, एक बार फिर उभरकर सामने आ गयी है। यूपीए-द्वितीय की सरकार के सत्यानाशी रिकार्ड से जन-असंतोष भड़का था और कांग्रेस के जनाधार में गिरावट आयी थी। कांग्रेस पार्टी का नवउदारवादी नीतियां अपनाना और इसके चलते पैदा हुआ भ्रष्टाचार ही इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इस पार्टी के अब भी इस गिरावट से उबर न पाने का पता महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड तथा जम्मू-कश्मीर के विधानसभाई चुनावों में उसकी पराजयों से चलता है। यह पार्टी नये नेतृत्व का चुनाव करने में संकट का सामना कर रही है।

क्षेत्रीय पार्टियां

2.49 पार्टी ने पिछले डेढ़ दशक में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका में आए बदलाव को दर्ज किया था। वर्गीय दृष्टि से क्षेत्रीय पार्टियां, अपने-अपने क्षेत्र के पूंजीपति वर्ग की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि ये पार्टियां मोटे तौर पर नवउदारवादी नीतियों का अनुमोदन कर रही हैं। पुनः ये पार्टियां अपने-अपने राज्यों में अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए, भाजपा और कांग्रेस के प्रति अवसरवाद तथा ढुलमुलपन का प्रदर्शन करती हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी ने भाजपा के साथ गठजोड़ किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, जिसका महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, उसके साथ नाता तोड़ लिया और विधानसभाई चुनाव के बाद भाजपा के साथ रब्त-जब्त करने की कोशिश की थी।

2.50 अन्नाद्रमुक तथा बीजू जनता दल ने लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन, लोकसभा चुनाव के बाद से ये दोनों ही पार्टियां भाजपायी सरकार-समर्थक रुख अपना रही हैं। बीजू जनता दल तथा अन्नाद्रमुक की क्रमशः ओडिशा तथा तमिलनाडु की सरकारें, नवउदारवादी नीतियों पर चल रही हैं। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक तथा द्रमुक, दोनों ही भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी हुई हैं, जिनमें उनके शीर्ष नेता संलिप्त हैं।

2.51 यह जरूरी है कि क्षेत्रीय पार्टियों की ऐसी राज्य सरकारों की नीतियों के खिलाफ लड़ा जाए जो जनविरोधी तथा मजदूर वर्गविरोधी रुख अपनाती हैं। यह भी जरूरी है कि प्रभुत्वशाली क्षेत्रीय पार्टियों की पूंजीवादी विचारधारा तथा राजनीति के खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाया जाए, ताकि अवाम को उनके प्रभाव के दायरे से निकालकर अपने साथ लाया जा सके।

2.52 एक जमाने के जनता दल से निकल कर आयी पार्टियां एकजुट होने के प्रयास कर रही हैं। सपा, राजद, जद (यू), जद (सेकुलर), आइ एन एल डी तथा सजपा, परस्पर विलय कर एक पार्टी बनाने की योजना बना रही हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो वे उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्तरी भारत के कुछ अन्य हिस्सों में एक कारगर शक्ति बन सकते हैं। बहरहाल, यह आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वे एक सुसंगत कार्यक्रम सूत्रबद्ध कर पाएंगे, जो अपनी सामाजिक व आर्थिक अंतर्वस्तु में जनवादी हो।

2.53 हमारी पिछली कांग्रेस के बाद से एक नयी राजनीतिक पार्टी सामने आयी है—आम आदमी पार्टी। इसका जन्म अन्ना हजारे के नेतृत्ववाले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन से हुआ था। आप पार्टी, दिल्ली के (2013 के) विधानसभाई चुनाव में और आगे चलकर लोकसभा चुनाव में पंजाब में, एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आयी थी। आप का अनेक जगहों पर मध्यवर्गीय हिस्सों पर तथा युवाओं के बीच असर पड़ा है। बहरहाल, जनता के मुद्दों पर आंदोलन करने के सिवा इस पार्टी ने अब तक न कोई स्पष्ट कार्यक्रम पेश किया है और न नीतियां।

जनसंघर्ष और जनांदोलन

2.54 सी पी आइ (एम) और वामपंथी पार्टियों ने खाद्य सुरक्षा के प्रश्न पर एक सतत अभियान चलाया था। ब्लाक स्तर से शुरू हुआ यह अभियान 2012 के जुलाई-अगस्त के दौरान दिल्ली में पांच दिन के जन-धरना तक पहुंचा था। आगे चलकर, सितंबर के महीने में जन-सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इसके बाद, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग को लेकर एक जन-हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में 3.5 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए गए। सी पी आइ (एम) तथा वामपंथी पार्टियों ने खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों के विनिवेश के खिलाफ अन्य गैर-कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों को गोलबंद करने के लिए भी पहल की। 20 सितंबर 2012 को एक देशव्यापी

हड़ताल तथा विरोध कार्रवाई का आयोजन किया गया, जो एक जोरदार विरोध कार्रवाई साबित हुई। पार्टी ने 30 दिसंबर 2012 को देश भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसाविरोधी दिवस का पालन किया और ऐसी हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदमों की मांग की।

2.55 पार्टी ने **संघर्ष संदेश जत्था** निकालकर हाल के दौर का अपना सबसे बड़ा जन-अभियान आयोजित किया। 2013 के मार्च के महीने में निकले चार जत्थों ने 11,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रास्ता तय किया। 19 मार्च को हुई विशाल रैली में यह अभियान अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। इस रैली ने 15 से 31 मई के बीच छः मांगों पर जन-सत्याग्रह का आह्वान किया। वामपंथी पार्टियों ने वैकल्पिक नीतियां सामने लाने के लिए 2013 की जुलाई में एक कन्वेंशन का आयोजन किया। इस मंच का संदेश जनता तक ले जाने के लिए विभिन्न राज्यों में रैलियों का आयोजन किया गया।

2.56 आने वाले दौर में पार्टी द्वारा जनसंघर्षों तथा जन-आंदोलनों के विकास पर जोर रहना चाहिए और जन-मोर्चों को भी जनता के विभिन्न तबकों को प्रभावित करने वाली समस्याओं व मुद्दों पर संघर्षों व आंदोलनों का आयोजन तथा नेतृत्व करना चाहिए। शक्तिशाली जनसंगठनों का निर्माण कर के ही पार्टी आगे बढ़ सकती है और वामपंथी तथा जनवादी शक्तियों को मजबूत बनाया जा सकता है।

2.57 नवउदारवादी नीतियों, सांप्रदायिकता तथा सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए जनांदोलनों का विकास और मजदूर वर्ग, किसानों, खेतमजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, आदिवासियों तथा दलितों के वर्गीय व जनसंगठनों का विकास जरूरी है। जनसंगठनों तथा उनके जन-प्रभाव का विस्तार, पार्टी की स्वतंत्र शक्ति के विस्तार और वामपंथी व जनवादी शक्तियों को गोलबंद करने की कुंजी है।

मजदूर वर्ग

2.58 तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा फैडरेशनों के संयुक्त मंच के झंडे तले जो संयुक्त संघर्ष विकसित हुआ है, उसे आगे ले जाया जाना चाहिए। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2013 की फरवरी में दो दिन की ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी। इस संयुक्त मंच को श्रम कानूनों के कमजोर किए जाने के खिलाफ संघर्ष चलाना चाहिए। कोयला खदान मजदूरों की दो दिन की हड़ताल, इसी एकता का फल थी।

2.59 मजदूर वर्गीय मोर्चे को केंद्रीय महत्व के उद्योगों में तथा नयी विनिर्माण इकाइयों में मजदूरों को संगठित करने पर अपने प्रयास केंद्रित करने चाहिए। उसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए और इन मजदूरों की विशाल संख्या को संगठित करना चाहिए। ट्रेड यूनियनों को मजदूर वर्गीय इलाकों में सामाजिक व शैक्षणिक गतिविधियां संगठित करनी चाहिए और सामाजिक मुद्दों को उठाना चाहिए। पार्टी को मजदूर वर्ग के रिहाइशी इलाकों में काम करने पर ध्यान देना चाहिए और सांप्रदायिक संगठनों की गतिविधियों की काट करने के लिए गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए।

किसान

2.60 कृषि के मोर्चे के संघर्षों तथा आंदोलनों को गरीब किसानों, खेतमजदूरों तथा ग्रामीण गरीबों की ओर उन्मुख होना चाहिए। किसानों के आंदोलन व संघर्ष संगठित करने तथा किसानविरोधी नीतियों के खिलाफ किसानों को गोलबंद करने में किसानों के विभिन्न तबकों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न फसलों तथा विभिन्न दौरों में कृषि संकट के प्रभाव की प्रकृति की भिन्नताओं को और भूस्वामियों व संपन्नतर तबकों के मजबूत विचारधारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। योजनाबद्ध तथा संकल्पबद्ध सांगठनिक काम के जरिए, सही नारे उठाने के जरिए और भूमि (भूमि अधिकारों के लिए तथा अंधाधुंध अधिग्रहण के खिलाफ), वनाधिकार, बटाईदारों के अधिकार के मुद्दों पर संघर्षों के निर्माण के जरिए, नवउदारवादी नीतियों व मुक्त व्यापार के प्रतिरोध के लिए तथा कृषि, पानी, बीज व वनों पर कार्पोरेट कब्जे के खिलाफ एवं लाभकारी दामों व ऋण सुविधाओं के विस्तार के लिए संघर्षों के जरिए, उक्त समस्याओं पर काबू पाना होगा।

खेतमजदूर

2.61 खेतमजदूर आंदोलन को रोजगार तथा मजदूरी, मनरेगा, प्रवासी मजदूरों, भूमि, वन क्षेत्रों, महंगाई व खाद्य सुरक्षा, घर के लिए जमीन, सामाजिक सुरक्षा, जातिवादी भेदभाव, महिला खेतमजदूरों के प्रश्न तथा खेतमजदूरों के लिए मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा के कदमों के लिए केंद्रीय कानून के मुद्दे उठाना जारी रखना चाहिए। आने वाले दौर में इन मुद्दों को उठाकर अधिकांश राज्यों में शक्तिशाली खेतमजदूर आंदोलन का निर्माण करना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में खेतमजदूरों के काम में स्पष्ट रूप से दिखाई देने

वाले बदलाव आए हैं। उनका ठोस तौर पर अध्ययन किया जाना चाहिए और ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने के लिए रणनीतियां विकसित की जानी चाहिए।

महिलाएं

2.62 महिलाओं व बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, उसका तकाजा है कि महिला संगठनों व ग्रुपों की एकजुट कार्रवाई के जरिए, व्यापक आधार पर एक प्रतिरोध विकसित करने के लिए व्यवस्थित तरीके से प्रयास किए जाएं। सांप्रदायिक ताकतों के हमले के साथ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यह हो जाता है कि महिलाओं के बीच हिंदुत्ववादी ताकतों की सांप्रदायिक व महिलाविरोधी विचारधारा तथा आचार की कैसे काट की जाए। इसे महिलाओं की तथा खासतौर पर महिलाओं के गरीब तबकों की जिंदगी तथा रोजी-रोटी पर नवउदारवादी नीतियों के ठोस प्रभावों के खिलाफ और ज्यादा संघर्षों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में महिला संगठन को भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के, जिसने बहुत ही जघन्य रूप ले लिया है, मुद्दे पर अपना काम तेज करना होगा और शहरी केंद्रों में युवतियों के वृहत्तर तबकों तक पहुंचने के लिए, जिन्हें यौन हमलों व उत्पीड़न का निशाना बनाया जा रहा है, तरीके निकालने होंगे।

युवा

2.63 युवाओं के रोजगार, आगे बढ़ने के लिए अवसरों के अभाव, खेल-कूद व सांस्कृतिक सुविधाओं की कमी और युवाओं का अराजनीतिकरण करने की सुनियोजित कोशिशों के मुद्दे उठाते हुए, युवा आंदोलन का विकास करना होगा। युवा मोर्चे को सामाजिक मुद्दे उठाने में सबसे आगे रहना चाहिए, जिससे युवाओं को जनतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष आदर्शों की भी प्रेरणा मिलेगी। इसे सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संवर्द्धित अभियान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

छात्र

2.64 यूपीए-द्वितीय के राज के दौरान छात्र मोर्चा शिक्षा के क्षेत्र के व्यापारीकरण तथा केंद्रीयकरण के खिलाफ संघर्ष करता रहा था। मोदी सरकार के आने के साथ, शिक्षा के क्षेत्र के संप्रदायीकरण के कदम उठाए जाने की शुरूआत हो गयी है। शिक्षा के लिए बजट आवंटन में कोई बढ़ोतरी न होने से, शिक्षा

का व्यापारीकरण बढ़ रहा है। छात्र आंदोलन का मुख्य जोर शिक्षा के व्यापारीकरण तथा संप्रदायीकरण के खिलाफ होना चाहिए। छात्रों के जनतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने पर जोर होना चाहिए। इन मुद्दों पर व्यापक आधारवाले संयुक्त आंदोलन खड़े किए जाने चाहिए। निजी शिक्षा संस्थाओं के बढ़ते हुए क्षेत्र से छात्रों को संगठित करने तथा आंदोलन में खींचने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

आदिवासी

2.65 आदिवासियों के एक अलग मंच के गठन से विभिन्न राज्यों में आदिवासियों के बीच काम में तेजी आयी है। इन राज्यों में वनाधिकार के पालन, विस्थापन, शिक्षा अधिकार, लघु वन उत्पादों पर आदिवासी महिलाओं के अधिकार से जुड़े प्रश्न तथा सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दे लिए गए हैं। स्थानीय संघर्षों को मजबूत करने तथा संगठन का निर्माण करने के जरिए इस काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आदिवासी मुद्दों पर वर्गीय रुख का सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुद्दों के साथ पूरा-पूरा योग किया जाना चाहिए। यह आदिवासी इलाकों में आर एस एस के हमले के खिलाफ कारगर साबित होगा।

दलित

2.66 दलितों के जातिवादी उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, जनतांत्रिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छुआछूत तथा जातिवादी भेदभाव के अन्य रूपों के खिलाफ संघर्ष; दलितों के लिए आरक्षण तथा कल्याणकारी कदमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष; अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना/विशेष घटक योजना के लागू कराए जाने के लिए कानूनी आधार के लिए संघर्ष और जाति व्यवस्था के खिलाफ वृहत्तर संघर्ष को आगे ले जाने की जरूरत है। दलित मंच के गठन से दलित मुक्ति आंदोलन को गति मिलनी चाहिए।

राजनीतिक लाइन

2.67 पार्टी को भाजपा तथा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ना है। यही आज का मुख्य काम है। इसके लिए मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का और उसकी हिंदुत्व-उन्मुख सामाजिक व शैक्षणिक नीतियों का सुसंबद्ध तरीके से विरोध जरूरी है। पार्टी को भाजपा-आर एस एस जोड़ी के खिलाफ राजनीतिक-विचारधारात्मक संघर्ष चलाना होगा। सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष, बाकी सब से काटकर नहीं चलाया जा सकता है।

उसका नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ और जनता की रोजी-रोटी की हिफाजत के लिए संघर्ष के साथ योग स्थापित करना होगा।

2.68 जहां संघर्ष की मुख्य दिशा भाजपा के खिलाफ है, हमारी पार्टी कांग्रेस का विरोध करती रहेगी। उसने नवउदारवादी नीतियां लागू की हैं और कांग्रेस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों तथा भ्रष्टाचार ने ही जनसमर्थन जुटाने में भाजपा की मदद की है। पार्टी, कांग्रेस के साथ कोई चुनावी तालमेल या गठबंधन नहीं करेगी।

2.69 नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का तकाजा है कि राज्य सरकारों द्वारा, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों की राज्य सरकारें भी शामिल हैं, लागू की जा रही इस तरह की नीतियों के खिलाफ भी संघर्ष चलाया जाए। मेहनतकश जनता को संगठित करने तथा उसे वामपंथी व जनवादी मंच के गिर्द गोलबंद करने के लिए भी यह जरूरी है कि क्षेत्रीय पार्टियों की पूंजीवादी-भूस्वामी राजनीति व नीतियों का राजनीतिक रूप से विरोध किया जाए।

2.70 पार्टी, सबसे बढ़कर अपनी स्वतंत्र शक्ति का विकास करने तथा निर्माण करने पर ध्यान देगी। इसके साथ ही साथ पार्टी जनता के मुद्दों पर, राष्ट्रीय संप्रभुता की हिफाजत के लिए, राज्यों के अधिकारों पर तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ अन्य जनतांत्रिक शक्तियों तथा गैर-कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ, एकजुट कार्रवाइयां विकसित करने के लिए प्रयत्न करेगी। अगर पार्टी को अपनी स्वतंत्र शक्ति का विस्तार करना है, तो जनांदोलनों तथा एकजुट संघर्षों के लिए संयुक्त मंच जरूरी हैं। वर्गीय तथा जनसंगठनों की एकजुट कार्रवाइयां कांग्रेस, भाजपा तथा अन्य पूंजीवादी पार्टियों के पीछे चलने वाली जनता को खींचने का प्रयत्न करेंगी।

2.71 पार्टी, वामपंथी व जनवादी शक्तियों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगी ताकि कदम-ब-कदम वामपंथी-जनवादी मोर्चे का निर्माण किया जा सके। यह एकजुट संघर्षों तथा संयुक्त आंदोलनों के निर्माण की प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता है। पार्टी की चुनावी कार्यनीति, खुद अपनी ताकत बढ़ाने के पार्टी के हितों से और वामपंथी तथा जनवादी शक्तियों को गोलबंद करने में मददगार होने से, संचालित होनी चाहिए।

वामपंथी एकता तथा आंदोलन

2.72 वामपंथी एकता की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर अब तक चार पार्टियों तक ही सीमित रही है—सी पी आइ (एम), सी पी आइ, फारवर्ड ब्लॉक तथा

आर एस पी। लोकसभा चुनाव के बाद से वामपंथी एकता को विस्तृत करने तथा मजबूत करने पर जोर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए छ: वामपंथी पार्टियां, जिनमें सी पी आइ (एमएल)-लिबरेशन तथा एस यू सी आइ (सी) शामिल हैं, 9 सूत्री मांगपत्र पर संयुक्त अभियान के लिए 2014 के दिसंबर में एकजुट हुईं। राज्यों में भी संयुक्त मंच विकसित हुए हैं। पंजाब में चार पार्टियां—सी पी आइ (एम), सी पी आइ, सी पी आइ (एमएल)-लिबरेशन तथा सी पी एम (पंजाब)—एक मांगपत्र पर संयुक्त आंदोलन के लिए एकजुट हुई हैं और 2014 के सितंबर से संयुक्त आंदोलन चला रही हैं।

2.73 पश्चिम बंगाल में 17 वामपंथी पार्टियां तथा ग्रुप साम्राज्यवाद तथा सांप्रदायिकता के खिलाफ संयुक्त कार्रवाइयों के लिए एकजुट हुए हैं। तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में 11 वामपंथी पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में हाल के विधानसभाई चुनाव में पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी एक बार फिर सी पी आइ (एम) तथा सी पी आइ के साथ आ गयी। वामपंथी एकता को और व्यापक बनाने और पार्टियों, ग्रुपों तथा व्यक्तियों को शामिल कर एक व्यापक वामपंथी मंच के निर्माण के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

वामपंथी आधार-क्षेत्र

2.74 पार्टी की 20वीं कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में दर्ज किया गया था कि पश्चिम बंगाल तथा केरल में लगे चुनावी धक्कों के चलते तथा अन्य राज्यों में पार्टी के कोई उल्लेखनीय प्रगति न कर पाने के चलते, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी तथा वामपंथ की स्थिति कमजोर हुई है। उसके बाद के दौर में पार्टी ने हालात पर और खासतौर पर पार्टी के तीन मजबूत राज्यों के सिलसिले में हालात को सुधारने की कोशिश की है।

2.74 पश्चिम बंगाल में 2009 से शुरू हुए सी पी आइ (एम) तथा वामपंथ के खिलाफ हिंसा तथा हमले जारी हैं। हिंसा तथा आतंक के पैमाने तथा दायरे के लिहाज से इन हमलों ने 1970 के दशक के हमलों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले तीन वर्षों में पार्टी की गतिविधियों को कुचलने तथा कार्यकर्ताओं को डराने के लिए हमलों के एक के बाद एक कई चक्र छेड़े गए हैं, मिसाल के तौर पर 2013 में पंचायत चुनाव के दौरान तथा उनके बाद और 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद हुई हिंसा, आदि। हमलों के इन एक के बाद एक आए चक्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को और

यहां तक कि पार्टी के लिए वोट डालने वालों तक को निशाना बनाया गया है। अनेक इलाकों में महिलाओं को इस हिंसा की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी है और उन्होंने हिम्मत के साथ हमलावरों का प्रतिरोध किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दायर करने के लिए सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं व सांसदों ने हिंसा, बलात्कार तथा हत्याओं के लिए उकसानेवाले भाषण दिए हैं। 2011 की मई में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी के 163 सदस्यों तथा समर्थकों की हत्या की गयी है।

2.76 राज्य के मौजूदा हालात की विशेषताएं हैं: तृणमूल कांग्रेस का कुशासन, शारदा घोटाला तथा उसमें तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की संलिप्तता, मजदूर वर्ग तथा किसानों की बिगड़ती दशा, महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपराध और लूट तथा जबरिया वसूली। तृणमूल कांग्रेस की अवसरवादी राजनीति और फासीवादी हरकतों ने भाजपा के आगे बढ़ने के लिए आधार तैयार किया है। हमारी पार्टी प्रतिकूल हालात पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। वह जनतंत्र व जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चला रही है, अपनी रोजी-रोटी के मुद्दों पर तथा आर्थिक समस्याओं पर संघर्ष करने के लिए जनता को गोलबंद कर रही है। इस तरह के अभियानों तथा संघर्षों को जनता से बढ़ता हुआ समर्थन मिल रहा है।

2.77 केरल में पार्टी तथा लेफ्ट-डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) द्वारा यूडीएफ सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष चलाए जाते रहे हैं। इस दौर में चलाए गए विभिन्न जनांदोलनों में सोलर पैनल घोटाले के सिलसिले में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर, लाखों लोगों का राज्य सेक्रेटेरियट का दो दिन तक घेराव किए रहना उल्लेखनीय है। पार्टी तथा एलडीएफ ने महंगाई के खिलाफ तथा खाद्य सुरक्षा के लिए और राज्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ आंदोलन चलाए हैं। एलडीएफ लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाया हालांकि, आर एस पी का पाला बदलना एक धक्का था। एलडीएफ को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

2.78 त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां पिछली कांग्रेस के बाद से पार्टी तथा वामपंथ के आधार का विस्तार हुआ है। 2013 की फरवरी में हुए विधानसभाई चुनाव में, लगातार पांचवीं बार वाम मोर्चा ने निर्णायक जीत हासिल की। वाम मोर्चा ने 52.3 फीसद वोट हासिल किया और कुल 60 में से 50

सीटों पर जीत हासिल की। 2014 की जुलाई में हुए तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी ने झाड़ूमार जीत पायी है। 95 फीसद से ज्यादा ग्राम पंचायतों में, 98.3 फीसद पंचायत समितियों में और 99 फीसद जिला परिषद सीटों पर, वाम मोर्चा को जीत हासिल हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में सी पी आइ (एम) ने 64.4 फीसद वोट हासिल कर, दोनों सीटें भारी बहुमत से जीत लीं। राज्य की वाम मोर्चा सरकार के अच्छे काम और सभी राजनीतिक व जन-मुद्दों पर पार्टी के हस्तक्षेप से, पार्टी के प्रभाव का विस्तार करने में मदद मिली है। इसे सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। भाजपा की केंद्र सरकार के हमलों से वाम मोर्चा सरकार की हिफाजत करने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है।

पार्टी को मजबूत करो तथा विस्तार दो

2.79 पार्टी की 20वीं कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया था:

''वर्तमान परिस्थितियों में, जब वामपंथ को गंभीर चुनावी धक्के लगे हैं और जब प0 बंगाल में, जहां पार्टी का सबसे मजबूत आधार है, पार्टी पर हमले हो रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अन्य राज्यों में पार्टी के प्रभाव तथा आधार का प्रसार किया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि पार्टी की स्वतंत्र भूमिका को मजबूत किया जाए तथा उसका विस्तार किया जाए। यही पार्टी को आगे ले जाने की कुंजी है। राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर पार्टी की स्वतंत्र गतिविधियां, अवाम को सक्रिय करने के लिए और आंदोलनों व संघर्षों में शामिल होने के लिए जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। जनसंगठनों को ऐसे स्वतंत्र मंच बनना चाहिए, जिनके आधार पर व्यापक आधारवाले आंदोलनों के लिए, जो उनके दायरे से बाहर के आवाम को भी अपनी लहर में खींच सकें, जनता को गोलबंद व संगठित किया जा सके।'' (पैरा 2.140)

2.80 इसकी वैधता बनी हुई है और मौजूदा परिस्थितियों में, खासतौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से, इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गयी है। संसद में हमारी घटी हुई ताकत तथा पार्टी के जनाधार के कमजोर होने के संदर्भ में, यह बहुत-बहुत जरूरी हो गया है कि पार्टी की स्वतंत्र भूमिका का विस्तार किया जाए और उसकी शक्ति तथा जनाधार में बढ़ोतरी की जाए। वर्गीय तथा जन-आंदोलनों के विकास पर पार्टी का जोर रहना

चाहिए। स्थानीय मुद्दों पर सतत संघर्षों का विकास, नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के साथ जोड़ने वाली कड़ी है।

2.81 पार्टी को अपने स्वतंत्र काम-काज के विकास के लिए, वर्गीय तथा जनसंगठनों को नेतृत्व मुहैया कराना चाहिए ताकि वे व्यापक आधारवाले आंदोलन तथा संघर्ष छेड़ सकें।

2.82 पूंजीवादी-भूस्वामी पार्टियों की राजनीति व विचारधारा का मुकाबला करने के लिए और सी पी आइ (एम) की राजनीतिक लाइन तथा वामपंथी तथा जनवादी कार्यक्रम के आधार पर उनकी काट करने के लिए, साहसपूर्ण पहल जरूरी है। पार्टी को हस्तक्षेप करना चाहिए और सामाजिक मुद्दों पर संघर्षों को हाथ में लेना चाहिए।

2.83 पार्टी को राजनीतिक तथा विचारधारात्मक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को सुसज्जित करना चाहिए ताकि वे राजनीतिक संघर्ष कर सकें और सत्ताधारी वर्गों की विचारधारा व राजनीति की काट कर सकें।

2.84 पार्टी को संगठन चुस्त-दुरुस्त करना होगा तथा नयी उन्मुखता देनी होगी ताकि वह राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कामों को संभाल सके और जुझारू संघर्ष चलाने में समर्थ हो।

वामपंथी तथा जनवादी मोर्चा

2.85 वामपंथी तथा जनवादी मोर्चा ही भाजपा, कांग्रेस तथा अन्य पूंजीवादी-भूस्वामी ताकतों का वास्तविक विकल्प है। यह उन वर्गों का मोर्चा है, जिन्हें जनता की जनवादी क्रांति के लिए गोलबंद करना होगा। इसलिए, यह मोर्चा सिर्फ चुनाव के लिए या सरकार बनाने के लिए बनाया जाने वाला गठबंधन भर नहीं हो सकता है बल्कि इसे ऐसी तमाम संघर्षशील ताकतों के मोर्चे के तौर पर सामने आना चाहिए जो मजदूर वर्ग, किसानों, खेतमजदूरों, मध्य वर्ग, दस्तकारों, दूकानदारों आदि का प्रतिनिधित्व करती हैं।

2.86 इस समय वामपंथी तथा जनवादी मोर्चे में खींची जा सकने वाली शक्तियों के केंद्र में हैं वामपंथी पार्टियां तथा उनके वर्गीय व जनसंगठन; वामपंथी ग्रुप तथा बुद्धिजीवी; विभिन्न पार्टियों में बिखरे हुए समाजवादी तथा गैर-कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के जनतांत्रिक हिस्से; आदिवासियों, दलितों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के जनतांत्रिक संगठन और ऐसे सामाजिक आंदोलन जो उत्पीड़ित तबकों के मुद्दे उठाते हैं। पूंजीवादी-भूस्वामी पार्टियों

से बिल्कुल भिन्न तथा उनकी नीतियों के विरोधी कार्यक्रम पर आधारित संयुक्त मंच पर इन सभी ताकतों को खींचने के जरिए ही, वामपंथी तथा जनतांत्रिक मोर्चे की दिशा में प्रगति एक ठोस रूप ले सकती है। एक साझा मांगपत्र के आधार पर विभिन्न वर्गीय तथा जनसंगठनों के एक साझा संगठन का निर्माण करना इसी दिशा में एक कदम होगा।

2.87 वामपंथी तथा जनवादी एकता के निर्माण का संघर्ष अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह से आगे बढ़ेगा। राज्यों में भांति-भांति की वामपंथी तथा जनवादी कतारबंदियां उभरकर सामने आएंगी, फिर भी वे अखिल भारतीय स्तर पर वामपंथी तथा जनवादी मोर्चे के निर्माण में योगदान करेंगी। पार्टी द्वारा अपनायी जाने वाली सभी कार्यनीतियां, एक मजबूत वामपंथी तथा जनवादी मोर्चे का निर्माण करने पर केंद्रित होनी चाहिए।

वामपंथी तथा जनवादी कार्यक्रम

2.88 वामपंथी तथा जनवादी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके दायरे में पूंजीवादी-भूस्वामी-नवउदारवादी खांचे की वैकल्पिक नीतियां आती हैं और जिसमें मजदूर वर्ग, किसानों, खेतमजदूरों, ग्रामीण मजदूरों, दूकानदारों, दस्तकारों, मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवियों की फौरी मांगें शामिल हैं। इस कार्यक्रम में शामिल मांगों तथा मुद्दों को वामपंथी तथा जनवादी ताकतों द्वारा राजनीतिक अभियानों, संघर्षों तथा जनांदोलनों का आधार बनाया जा सकता है।

2.89 इस कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(1) विकास के ऐसे रास्ते के लिए जो विश्व अर्थव्यवस्था से नाता रखते हुए भी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएगा, उत्पादक शक्तियों का विकास करेगा, रोजगार को अधिकतम बनाएगा और आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को घटाएगा। नियोजित विकास होना चाहिए, जिसके साथ विकेंद्रीकरण का योग हो।

(2) मुकम्मल भूमि सुधारों के लिए तथा कृषि संबंधों के जनतांत्रिक रूपांतरण के लिए; सहकारी खेती व मार्केटिंग का विकास।

(3) इजारेदारियों पर अंकुश, अतिमहत्वपूर्ण उद्योगों तथा बुनियादी सेवाओं में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन, संपदा का पुनर्गठन करने के लिए राजकोषीय व कर संबंधी कदम।

(4) संविधान के बुनियादी सिद्धांत के रूप में धर्म तथा शासन के अलगाव का रोपा जाना। केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन के साथ एक जनतांत्रिक

तथा संघीय ढांचा।

(5) **मजदूर वर्ग:** मजदूरों के लिए कम से कम 15,000 रु0 की वैधानिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना तथा मजदूरी का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना; गुप्त मतदान के जरिए ट्रेड यूनियनों को मान्यता दिया जाना सुनिश्चित करना; सामाजिक सुरक्षा तथा प्रबंधन में मजदूरों की हिस्सेदारी की गारंटी। रोजगार के ठेकाकरण का अंत।

(6) **किसान:** किसानी खेती की वहनीयता सुनिश्चित करने तथा खेती को लाभकारी बनाने के लिए कदम। व्यापारिक गैर-कृषि कार्यों के लिए अधिग्रहण से कृषि भूमि की हिफाजत। कार्पोरेट खेती तथा निजीकरण पर रोक।

(7) **खेतमजदूर:** खेतमजदूरों के लिए मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रीय कानून; घर बनाने के लिए जमीन, और ग्रामीण मजदूरों के लिए आवास।

(8) **शिक्षा तथा छात्र-छात्राएं:** शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसद हो; सैकेंडरी स्तर तक मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो; गुणवत्ता तथा विस्तार, दोनों ही पहलुओं से सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए; निजी शैक्षणिक संस्थाओं में फीस तथा पाठ्यक्रम का नियमन किया जाए।

(9) **युवा:** संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में काम का अधिकार। अपने चौतरफा विकास के लिए युवाओं के लिए—खेल-कूद, संस्कृति तथा कौशल प्रशिक्षण की—सेवाओं का प्रावधान।

(10) **स्वास्थ्य:** स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 5 फीसद के बराबर किया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जाए तथा उसका विस्तार किया जाए; निजी स्वास्थ्य केंद्रों का नियमन किया जाए; मूल्य निर्धारण का लागत पर आधारित फार्मूला अपना कर आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाया जाए।

(11) **पर्यावरण:** कारगर नियमन, उत्पादन व उपभोग के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा कुशलता लाने के जरिए, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए कदम उठाए जाएं। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। ऊर्जा असमानता को घटाया जाए। नदियों तथा जलाशयों के प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाए। जल स्रोतों का कोई निजीकरण नहीं होना चाहिए।

(12) **जनकल्याण:** खाद्यान्नों के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी

आपूर्ति के साथ सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वभौम पेंशन लाभ। पीने के लिए सुरक्षित पानी तथा जल-मल निकासी की व्यवस्था। शहरी गरीबों के लिए आवास।

(13) **महिला:** संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान। महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को रोकने, उन पर अंकुश लगाने तथा उनके दोषियों को सजा दिलाने के लिए कदमों का लागू किया जाना।

(14) **दलित:** जाति व्यवस्था तथा हर प्रकार के जातिवादी उत्पीड़न का अंत। छुआछूत के व्यवहार तथा अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचारों के लिए कड़ी सजा। आरक्षित सीटों पर, पदों पर तथा पदोन्नतियों में बैकलॉग का भरा जाना। दलित ईसाइयों के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा। निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण।

(15) **आदिवासी:** आदिवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा और अवैध रूप से उनसे हथियाई गयी जमीनें उन्हें वापस दिलाना। वनाधिकार कानून का पूरा-पूरा पालन। लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य।

(16) **अल्पसंख्यक:** अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण के विशेष प्रावधान।

(17) **बच्चों के अधिकार:** बाल श्रम के सभी रूपों पर प्रतिबंध। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास योजना (आइसीडीएस)/शिशु देख-रेख की सार्वभौम व्यवस्था।

(18) **विकलांग:** अधिकार-आधारित ढांचा। संविधान में संशोधन कर विकलांगता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करना। समान अवसर तथा मैदान में बराबरी के मौके। सभी सार्वजनिक जगहों तक बाधामुक्त पहुंच।

(19) **जनतांत्रिक अधिकार तथा चुनाव सुधार:** आंशिक सूची के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चुनावों में वस्तुओं के रूप में सरकारी फंडिंग का प्रावधान। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां कानून को निरस्त करना। अवैध गतिविधियां निवारण कानून में सुधार करना। भारतीय दंड संहिता से राजद्रोह संबंधी प्रावधान हटाना। मौत की सजा का अंत।

(20) **संस्कृति और मीडिया:** बाजार-संचालित मूल्यों के विकृतीकरणकारी असर से मुक्त जनतांत्रिक संस्कृति का विकास। प्रतिगामी सांप्रदायिक

तथा पोंगापंथी प्रभावों की काट करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष तथा मिली-जुली संस्कृति का विकास। लोक कलाओं तथा परंपराओं का पोषण। सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को मजबूत करना। मीडिया में एकाधिक क्षेत्रों में स्वामित्व पर रोक। मीडिया के लिए एक स्वतंत्र नियमन प्राधिकार।

2.90 काम

(1) दक्षिणपंथी हमले के खिलाफ आमने-सामने की लड़ाई लड़नी होगी। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का, जोकि नवउदारवादी मुहिम का ही हिस्सा हैं, डटकर विरोध किया जाना चाहिए। मेहनतकश जनता पर नवउदारवादी हमले की सभी अभिव्यक्तियों का, मेहतनकश जनता के विभिन्न तबकों को संगठित तथा गोलबंद कर प्रतिरोध किया जाना चाहिए।

(2) आर एस एस-भाजपा गठजोड़ के हिंदुत्व के एजेंडा का राजनीतिक रूप से और पार्टी तथा जनसंगठनों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, विचारधारात्मक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर भी, मुकाबला किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक खतरे के खिलाफ तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की हिमायत में, धर्मनिरपेक्ष तथा जनतांत्रिक शक्तियों की व्यापकतम गोलबंदी की जानी चाहिए।

(3) पार्टी को अविचल रूप से साम्राज्यवादविरोधी एजेंडा को उठाना चाहिए। अमरीका के साथ बढ़ते रणनीतिक रिश्तों के खिलाफ और अमरीका के दबावों के सामने शासक वर्ग द्वारा समर्पण किए जाने के खिलाफ, जनता को गोलबंद करना इसमें शामिल है। दुनिया भर में सभी साम्राज्यवादविरोधी संघर्षों के लिए समर्थन।

(4) पार्टी को सामाजिक रूप से उत्पीड़ित तबकों, दलितों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रखवाली के अपने प्रयास तेज करने चाहिए। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और महिलाओं पर बढ़ते हमलों का मुकाबला करने के लिए पार्टी को सीधे हस्तक्षेप करना होगा।

(5) जनतांत्रिक अधिकारों व कलात्मक अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रताओं की हिफाजत के लिए और संसदीय जनतंत्र पर अंकुशों के विरुद्ध एक व्यापक गोलबंदी के जरिए, दक्षिणपंथी बदलाव से पैदा होने वाले तानाशाहीपूर्ण खतरे के खिलाफ लड़ना होगा।

(6) पश्चिम बंगाल में पार्टी तथा वामपंथ को हिंसा से तथा जनतंत्र पर

हमलों से बचाने के संघर्ष को, जनतंत्र तथा जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक अखिल भारतीय अभियान की मदद हासिल होनी चाहिए। वामपंथी तथा जनवादी ताकतों को प्रतिक्रियावादी ताकतों के हमलों से तथा केंद्र सरकार के शत्रुभाव से त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार की हिफाजत करनी चाहिए।

(7) पार्टी को अपनी स्वतंत्र भूमिका के विस्तार और अपनी शक्ति व जनाधार को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पार्टी को वर्गीय व जन-मुद्दों पर एकजुट कार्रवाइयों पर जोर देना चाहिए। वर्गीय तथा जनसंगठनों को एकजुट संघर्षों व आंदोलनों से इसके लिए वेग मिलना चाहिए कि पूंजीवादी पार्टियों के अनुयाइयों को अपनी ओर खींच सकें।

(8) वामपंथी तथा जनवादी कार्यक्रम के गिर्द विभिन्न वर्गों तथा मेहनतकशों को गोलबंद कर, वामपंथी एकता का निर्माण तथा विस्तार, ताकि वामपंथी तथा जनवादी मोर्चे के निर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सके।

एक शक्तिशाली पार्टी के निर्माण का आह्वान

2.91 देश के सामने मौजूद नाजुक हालात में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सी पी आइ (एम) का निर्माण किया जाए तथा उसे ताकतवर बनाया जाए। आइए, हम ऐसी एक शक्तिशाली पार्टी के निर्माण की ओर बढ़ें:

★ मेहनतकश जनता के सभी तबकों के संघर्षों को चलाने के लिए एक पार्टी को जीवंत तथा जुझारू संगठन बनाएं;

★ पार्टी की मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारात्मक नींवों को मजबूत करें;

★ तय किए गए कामों को पूरा करने के लिए संगठन को नयी उन्मुखता दें तथा मजबूत करें।

आइए, जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय तथा समाजवाद के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएं!

नवउदारवादी पूंजीवाद और बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिकता द्वारा बरपा किए जा रहे कहर से सिर्फ वामपंथी तथा जनवादी विकल्प ही देश को बचा सकता है।

आइए, एक मजबूत वामपंथी तथा जनवादी मोर्चे के निर्माण की ओर चलें।

21वीं कांग्रेस समूची पार्टी का आह्वान करती है कि इस संदेश को जनता के बीच ले जाएं। □

राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे में संशोधन कैसे भेजें ?

राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे में संशोधन भेजने का तरीका इस प्रकार है:

1. हरेक संशोधन पैरा क्रमांक/पंक्ति क्रमांक अवश्य लिखें।
2. संशोधन का प्रस्ताव करने वाले कामरेड/यूनिट का नाम अवश्य लिखें।
3. सारे संशोधन प्रस्ताव 25 मार्च 2015 तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।
4. डाक/कूरियर से भेजे जाने वाले संशोधन प्रस्तावों के लिए पता इस प्रकार है:

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
केंद्रीय कमेटी, ए के गोपालन भवन
27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001

5. लिफाफे पर 'राजनीतिक प्रस्ताव का मसौदा' अवश्य लिखें।
6. फैक्स संदेश अस्पष्ट आते हैं, साथियों को फैक्स से संशोधन भेजने से बचना चाहिए।
7. ई-मेल से संशोधन भेजने वाले साथियों से अनुरोध है कि टैक्स्ट या वर्ड फाइल के रूप में ही अपने संशोधन भेजें। अंगरेजी से इतर अन्य भाषाओं में संशोधन प्रस्ताव भेजने वाले साथी पी डी एफ फाइल ही भेजें।
8. ई-मेल संदेशों में विषय में—Amendments to the Draft Poliical Resolution लिखें और pol@cpim.org पर भेजें।
9. संशोधन प्रस्ताव अगर नीचे दिए प्रारूप में भेजे जाएं तो सुविधा होगी:

क्र0	पैरा	लाइन	संशोधन	प्रस्तावक
1				
2				
3				

फरवरी 2015 **मूल्य : 10 रुपये**

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लिए हरि सिंह कांग द्वारा ए के गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित